CNEWS सिटी चीफ

सिटी चीफ

वर्ष-15, अंक-63
पृष्ठ-8 मूल्य 2 रूपया

सम्पूर्ण भारत मे चर्चित हिन्दी अखबार

CITYCHIEFSENDMENEWS@GMAIL.COM

इंदौर, रविवार, 09 जून 2024

आज का विचार

प्रसन्न व्यक्ति वह है,जो निरन्तर स्वयं का मूल्यांकन करते हुए सुधार करता है.

जबकि दुखी व्यक्ति वह है, जो सिर्फ दूसरों का मूल्याकंन करते हुए हर समय उनकी बुराई, आलोचना,निन्दा एवं ईर्ष्या करता है!

मोदी शाम 7:15 बजे शपथ लेंगे, पंडित नेहरू के 62 साल पुराने रिकॉर्ड की बराबरी करेंगे

प्रधानमंत्री मोदी का शपथ ग्रहण समारोह होगा यादगार

मालदीव के राष्ट्रपति सहित कई राष्ट्राध्यक्ष और विदेशी मेहमानों के साथ कई खास मेहमान होंगे शामिल

नई दिल्ली प्रधानमंत्री मोदी ने अपने दिन की शुरुआत राजघाट में महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देकर की। वे यहां से पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की समाधि सदैव अटल और फिर नेशनल वॉर मेमोरियल गए। मोदी 3.0 के संभावित मंत्रियों को फोन पहुंचना शुरू हो गए हैं। शपथ से पहले सभी मंत्रियों के साथ पीएम मोदी चाय पर चर्चा करेंगे।इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह महात्मा गांधी और पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की समाधि पहुंचे। उन्हें श्रद्धांजलि दी। इसके बाद प्रधानमंत्री ने वॉर मेमोरियल जाकर शहीदों को नमन किया। वे आज शाम 7:15 बजे राष्ट्रपति भवन में प्रधानमंत्री पद की तीसरी बार शपथ लेंगे।शपथ लेने के साथ ही मोदी पूर्व पीएम पंडित जवाहर लाल नेहरू के लगातार तीन बार प्रधानमंत्री बनने के 62 साल पुराने रिकॉर्ड की बराबरी कर लेंगे। नेहरू 1952, 1957 और 1962 में लगातार 3 बार विजयी होकर पीएम बने थे। हालांकि, नेहरू की सरकार पूर्ण बहुमत की थी। मोदी की तीसरी पारी गठबंधन की बुनियाद पर चलेगी। देश में 1990 के दशक से गठबंधन की राजनीति चल रही थी। इस चलन को मोदी के नेतृत्व में भाजपा ने 2014 और 2019 में पूर्ण बहुमत हासिल करके तोड़ा था। हालांकि, 2024 में भाजपा 240 सीटों पर सिमट गई और बहुमत के लिए अपने सहयोगी दलों की जरूरत पड़ी।7 जून को संसद के सेंट्रल हॉल में हुई मीटिंग में ND नेताओं ने मोदी को अपना नेता चुन लिया। अब शपथ का इंतजार है। समारोह में चीन, पाकिस्तान और अफगानिस्तान को छोड़कर 7 पड़ोसी देशों- श्रीलंका, बांग्लादेश, मालदीव, सेशेल्स, मॉरिशस, नेपाल और भूटान के राष्ट्र प्रमुख शामिल होंगे।

इन लोगों ने निमंत्रण किया स्वीकार

श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे, मालदीव के राष्ट्रपति डॉ. मोहम्मद मुइज्जु, सेशेल्स के उपराष्ट्रपति अहमद अफीफ, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री, शेख हसीना, मॉरीशस के प्रधानमंत्री प्रविंद कुमार जगन्नाथ, नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड और भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग तोबगे ने प्रधानमंत्री मोदी के शपथ ग्रहण समारोह का निमंत्रण स्वीकार कर लिया है। यह भी बताया जा रहा है कि शपथ ग्रहण समारोह में भाग लेने के अलावा यह सभी नेता उसी शाम राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा आयोजित भोज में भाग लेंगे।

नरेंद्र मोदी तीसरे कार्यकाल के लिए 9 जून को राष्ट्रपति भवन में प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। प्रधानमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह कई मायनों में बेहद खास होगा। इस समारोह में जहां एक तरफ दुनियाभर के शीर्ष नेता शामिल होंगे, तो वहीं सफाईकर्मी, ट्रांसजेंडर, मजदूर भी इस ऐतिहासिक पल के साक्षी बनेंगे। नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में कुल 8000 मेहमान शामिल हो सकते हैं। इस शपथ ग्रहण समारोह में दुनिया के कई शीर्ष नेता शामिल हो सकते हैं। भारत के पड़ोस और हिंद महासागर क्षेत्र के नेताओं को विशिष्ट अतिथि के रूप में सादर आमंत्रित किया गया है। मालदीव के मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार, राष्ट्रपति मुइज्जू शनिवार को नई दिल्ली के लिए रवाना होंगे और इस दौरान उनके साथ उनकी सरकार के कई वरिष्ठ अधिकारी भी भारत आएंगे। हालांकि अभी तक मालदीव की सरकार की तरफ से इसे लेकर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है।

जमीन से लेकर आसमान तक हाई सिक्योरटी के बीच शपथ लेंगे मोदी, नो ड्रोन, नो फ्लाई जोन के बीच होगा समारोह

पीएम नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। राजधानी दिल्ली को हाई अलर्ट पर रखा गया है। इस समारोह को ध्यान में रखते हुए दिल्ली पुलिस ने 9 और 10 जून को नो फ्लाई जोन घोषित किया है। इस दौरान सेफ्टी के लिए एसपीजी, राष्ट्रपति के सुरक्षा गार्ड, आईटीबीपी, दिल्ली पुलिस, खुफिया विभाग की टीमें, अर्द्धसैनिक बलों के जवान, एनएसजी के ब्लैक कैट कमांडो और एनडीआरएफ की टीमें मौजूद होंगी। इसके साथ ही ऊंची इमारतों में एंटी ड्रोन सिस्टम भी तैनात किए जा रहे हैं। इसके अलावा खुफिया जगहों और ऊंची इमारतों पर स्नाइपर्स की तैनाती भी रहेगी। सेफ्टी को लेकर कहा जा रहा है कि जी-20 के दौरान अपनाए गए स्टैंडर्ड मानकों को अपनाया जाएगा।

टीडीपी के 4 और जेडीयू के 2 मंत्री ले सकते हैं शपथ

नई दिल्ली। 9 जून को पीएम के साथ नई सरकार के मंत्रिमंडल का भी शपथ ग्रहण होगा। इससे पहले मोदी सरकार 3.0 में मंत्रालय को लेकर चर्चा तेज हो गई है। चूंकि इस बार बीजेपी अपने दम पर सरकार नहीं बना पाई है इसलिए एनडीए के सहयोगी दलों टीडीपी और जेडीयू के हिस्से में मंत्री पद मिलना तय माना जा रहा है। सूत्रों के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाले नए कैबिनेट में चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी को चार मंत्रालय मिलेंगे, जबकि जेडीयू को दो मंत्रालय मिलेंगे। सूत्रों के मुताबिक, मोदी के नए कैबिनेट में जगह पाने वाले चार टीडीपी नेताओं में से तीन राम मोहन नायडू, हरीश बालयोगी और डग्गुमल्ला प्रसाद हैं। वहीं नीतीश कुमार की जेडयू ने दो सीनियर नेताओं ललन सिंह और राम नाथ ठाकुर के नाम प्रस्तावित किए हैं। ललन सिंह बिहार के मुंगेर से लोकसभा सांसद चुने गए

थे, जबकि राम नाथ ठाकुर राज्यसभा सांसद हैं। राम नाथ ठाकुर भारत रत्न कपूरी ठाकुर के बेटे हैं।

एनडीए की कैबिनेट को लेकर हुई बैठक शपथ ग्रहण से पहले शनिवार को कैबिनेट में मंत्रालयों को लेकर एनडीए की बैठक हुई। सूत्रों के अनुसार, बैठक में टीडीपी ने आंध्र प्रदेश में 16 लोकसभा सीटें जीतने के बाद चार मंत्रालय और संसद के स्पीकर का पद मांगा था। वहीं जेडीयू ने 12 सीटें जीतने के बाद दो कैबिनेट मंत्रालय मांगे। हालांकि अभी तक इसे लेकर खुलकर किसी भी पार्टी ने कुछ नहीं कहा है।

लोकसभा चुनाव में बीजेपी अपने दम पर बहुमत हासिल नहीं कर पाई। बीजेपी ने केवल 240 सीटें जीती। जबकि सरकार बनाने के लिए 272 सीटों की जरूरत थी। हालांकि एनडीए गठबंधन ने बहुमत हासिल कर लिया। सरकार बनाने में चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार किंगमेकर के रूप में उभरे। हालांकि अब दोनों नेता कैबिनेट को लेकर बीजेपी से अपनी मांगे मनवाने की कोशिश में लगे हुए हैं।

कांग्रेस संसदीय दल की नेता चुनी गईं सोनिया गांधी, खरगे के प्रस्ताव पर लगी मुहर

नई दिल्ली। संसद के सेंट्रल हॉल में शनिवार को कांग्रेस संसदीय दल की बैठक हुई। बैठक में सोनिया गांधी को कांग्रेस संसदीय दल की नेता चुन लिया गया। बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे सोनिया गांधी के नाम का प्रस्ताव रखा था, जिसे सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया। इस बैठक में सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खरगे, पार्टी सांसद राहुल गांधी, प्रमोद तिवारी और पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेता मौजूद रहे।

इससे पहले शनिवार को ही राजधानी दिल्ली में कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक हुई। बैठक में पार्टी के भविष्य की रणनीति तय करने के लिए लोकसभा चुनाव परिणामों पर महत्वपूर्ण विचार-विमर्श किया गया। बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने कांग्रेस संसदीय दल के अध्यक्ष पद के लिए सोनिया गांधी के नाम का प्रस्ताव रखा। पार्टी सांसद गौरव गोगोई, तारिक अनवर, के सुधाकरन ने प्रस्ताव का समर्थन किया। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी ने जानकारी देते हुए कहा, सोनिया गांधी को सर्वसम्मति से कांग्रेस संसदीय दल का अध्यक्ष चुना गया है।

राहुल गांधी लोकसभा में बनें नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस वर्किंग कमेटी में प्रस्ताव पास

नई दिल्ली।कांग्रेस वर्किंग कमेटी (सीडब्ल्यूसी) ने राहुल गांधी से लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष बनने को लेकर प्रस्ताव पास किया है। संगठन के प्रभारी पार्टी महासचिव केसी वेणुगोपाल ने शनिवार को यह जानकारी दी। उन्होंने कहा, सीडब्ल्यूसी ने सर्वसम्मति से राहुल गांधी से लोकसभा में विपक्ष के नेता की भूमिका निभाने की अपील की। संसद के अंदर इस कैंपेन को लीड करने के लिए राहुल जी सबसे सही व्यक्ति हैं। वेणुगोपाल से पूछा गया कि इस प्रस्ताव को लेकर राहुल गांधी की क्या प्रतिक्रिया रही? उन्होंने बताया, इस पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने कहा कि वह विचार करेंगे।कांग्रेस की सीडब्ल्यूसी बैठक के बाद कांग्रेस नेता भूपेंदर सिंह हुड्डा की भी प्रतिक्रिया आई। उन्होंने कहा, राहुल गांधी को नेता प्रतिपक्ष बनाना चाहिए। यही

सबकी मांग है और यही कांग्रेस को मजबूती देगी। मीटिंग के बाद कांग्रेस नेता गौरव गोगोई ने कहा, जब भी कांग्रेस पार्टी ने राहुल गांधी से कुछ अपेक्षा की है तो उन्होंने पार्टी की ख्वाहिश पूरी की है। आज कांग्रेस पार्टी उनसे गुजारिश करती है कि वो देश की आवाज सदन में उठाएं। वहीं, कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि सबने यही बोला है कि राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष बनें। यही होना भी चाहिए।

कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव में जीतीं 99 सीटें निचले सदन में पार्टी संसदीय दल का नेता ही नेता प्रतिपक्ष होगा। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव में 99 सीटें जीती हैं। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे की अध्यक्षता में विस्तारित कांग्रेस कार्य समिति की बैठक हुई। इसमें लोकसभा चुनाव में मल्लिकार्जुन खरगे, पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी और महासचिव प्रियंका गांधी के योगदान की सराहना भी की गई। इसको लेकर प्रस्ताव भी पारित किया गया। विस्तारित कार्य समिति की बैठक में पार्टी संसदीय दल की प्रमुख सोनिया गांधी, पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, महासचिव प्रियंका गांधी वाद्रा, संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल और कार्य समिति के अन्य सदस्य व वरिष्ठ नेता मौजूद रहे।

संशोधित हो सकता है 1600 छात्रों का नीट का रिजल्ट

शिक्षा मंत्रालय ने ग्रेस मार्क्स मामले की जांच के लिए बनाई चार सदस्यीय कमेटी

नई दिल्ली। मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट के रिजल्ट में कथित गड़बड़ी के बाद मचे हंगामे और सीबीआई जांच की मांग के बीच नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) ने शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि शिक्षा मंत्रालय ने ग्रेस मार्क्स मामले की जांच के लिए चार सदस्यीय कमेटी बनाई है। यूपीएससी के पूर्व चेयरमैन की अगुवाई में यह कमेटी एक सप्ताह के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। यह समिति परीक्षा केंद्र से रिपोर्ट, सीसीटीवी फुटेज सहित समय की बबार्दी के डिटेल्स पर गौर करेगी।

एनटीए ने कहा कि स्टूडेंट्स को ग्रेस अंक देने से नतीजों या क्वालिफाइंग क्राइटेरिया में कोई फर्क नहीं पड़ा है। एनटीए ने पेपर लीक होने के आरोपों को भी खारिज कर दिया। एनटीए डीजी सुबोध कुमार सिंह ने कहा

यह मसला सिर्फ 1600 स्टूडेंट्स का मसला है। पेपर 23 लाख से ज्यादा बच्चों ने दिया था। 4750 सेंटर की बजाय सिर्फ 6 सेंटर का मामला है। कमेटी इन करीब 1600 स्टूडेंट्स को दिए गए ग्रेस मार्क्स व टाइम लॉस मामले की जांच करेगी। जरूरत पड़ेगी तो इनका रिजल्ट संशोधित किया जा सकता है। इससे नीट रिजल्ट के बाद होने वाली एमबीबीएस व बीडीएस समेत विभिन्न मेडिकल कोर्सेज की एडमिशन प्रक्रिया पर कोई असर नहीं पड़ेगा। कमेटी की जो सिफारिशें आएंगी, हम फैसला लेंगे। पेपर लीक के आरोपों पर अधिकारियों ने कहा, सोशल मीडिया पर जो पेपर आया, वह पेपर शुरू होने के बाद आया था। हम भविष्य में अपने प्रोटोकॉल व स्टैंडर्ड को और मजबूत बनाएंगे ताकि फिर से इस तरह की गलती फिर से नहीं हो।

सीएम योगी ने मंत्रियों को दिए जनता के बीच जाने के निर्देश

वीआईपी कल्चर से परहेज करें मंत्री-जनप्रतिनिधि

लखनऊ। लोकसभा चुनाव के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ का एक्शन शुरू हो गया है। शनिवार को मंत्रिमंडल की बैठक में उन्होंने मंत्रियों को जनता के बीच जाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि मंत्री हो या कि अन्य जनप्रतिनिधि, सभी को वीआईपी कल्चर से परहेज करें। हमारी कोई भी गतिविधि ऐसी न हो, जो वीआईपी संस्कृति को प्रदर्शित करती हो, इसके लिए सभी को सतर्क और सावधान रहना होगा।

सीएम ने कहा कि सरकार जनता के लिए है। हमारे लिए जनहित सर्वोपरि है, ऐसे में समाज के

अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति की समस्याओं, अपेक्षाओं और आवश्यकताओं का समाधान होना ही चाहिए। उन्होंने कहा कि संवेदनशीलता के साथ जनता से संवाद करें और स्थानीय जनप्रतिनिधियों, शासन-प्रशासन के साथ समन्वय बनाते हुए समस्याओं का समाधान करें। जहां भी समस्या हो, मुख्यमंत्री कार्यालय को बताया जाए। वहां से पूरा सहयोग मिला।

सरकार की नीतियां जन तक पहुंचाने के निर्देश मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लगातार तीसरी बार केंद्र में सरकार बनने पर बधाई दी। साथ ही, सांसद निर्वाचित होने वाले मंत्रियों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के 10 वर्षों में जिस तरह उत्तर प्रदेश में विकास को रफ्तार मिली है, आने वाले पांच वर्षों में हम अनेक नए कीर्तिमान रचने में सफल होंगे। सभी मंत्री केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियों का व्यापक प्रचार-प्रसार करें। सोशल मीडिया पर सक्रियता बढ़ाएं। डबल इंजन सरकार की नीतियों, निर्णयों और उनके सकारात्मक परिणाम से जनता को अवगत कराएं।

सिंगल कॉलम

देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी ने घोषित किए पीजी कोर्स की परीक्षाओं के रिजल्ट

इंदौर। देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी ने पीजी कोर्स की परीक्षाओं के रिजल्ट घोषित कर दिए हैं। इसमें एमएससी, एमए और एलएलएम के रिजल्ट शामिल है। स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर रिजल्ट देख सकते हैं। रिजल्ट में देरी की वजह से स्टूडेंट्स परेशान हो रहे थे। पंद्रह-बीस दिन में स्टूडेंट्स को मार्कशीट मिल जाएगी। एटीकेटी और फेल स्टूडेंट रिव्यू के लिए आवेदन कर सकते हैं। एलएलएम पहले सेमेस्टर का रिजल्ट 7 महीने से रुका हुआ था, जिसे यूनिवर्सिटी ने जारी किया है। लगभग 37 परसेंट स्टूडेंट्स के नंबर में बदलाव हुआ है। यूनिवर्सिटी एडमिशन प्रोसेस को देखते हुए ग्रेजुएशन अंतिम वर्ष के रिजल्ट जारी करने पर फोकस कर रही है। जिससे स्टूडेंट्स को पीजी में एडमिशन लेने में परेशानी नहीं आए। कॉपियों की चेकिंग का काम चल रहा है। अधिकारियों की माने तो अगले बीस दिन में बीए, बीकॉम, बीएससी के रिजल्ट घोषित हो जाएंगे, क्योंकि जिन स्टूडेंट्स को एटीकेटी आएगी उनकी एक्जाम भी यूनिवर्सिटी को समय पर करानी होगी।

मालवा-निमाड़ के तीन सांसद भी मंत्रीपद की दौड़ में

इंदौर। एनडीए सरकार के मंत्रिमंडल में शामिल होने वालों में मालवा निमाड़ के दो से तीन बार लगातार चुनाव जीते सांसद सुधीर गुप्ता, गजेंद्र पटेल, शंकर लालवानी भी दौड़ में है। उन्हे जातिगत समीकरणों पर भरोसा है। फिलहाल मालवा निमाड़ के सांसद भी दिल्ली में डेरा डाले हुए है और मंत्री बनने की संभावनाएं टटोल रहे हैं।

मालवा निमाड़ के आठों लोकसभा क्षेत्रों से भाजपा उम्मीदवार लाखों मतों के मार्जिन से जीते है। सांसद सुधीर गुप्ता ने जीत की हैट्रिक लगाई है और चार लाख से ज्यादा वोटों के अंतर से जीत दर्ज कराई है। गुप्ता वैश्य समाज से आते है। वरिष्ठता के नेता वे भी मंत्री पद की उम्मीद लगाए हुए है। देश में सबसे ज्यादा वोटों से जीतने वाले शंकर लालवानी दूसरी बार सांसद बने है। वे सिंधी समाज से आते है। सिंधी समाज भाजपा का वोटबैंक माना जाता है। लालवानी के लिए समाज के राष्ट्रीय संगठन भी लाबिंग कर रहे है। आदिवासी समाज से आने वाले गजेंद्र पटेल भी खरगोन लोकसभा सीट से दूसरी बार चुनाव जीते है, हालांकि आठों विधानसभा सीट में उनके वोटों का मार्जिन सबसे कम था। अनुसूचित जाति कोटे से अनिल फिरोजिया और देवास सांसद महेंद्र सोलंकी भी मंत्रीपद की कोशिश में जुटे है। दोनो दूसरी बार सांसद बने है। केंद्रीय मंत्रीमंडल में मालवा निमाड़ का हमेशा से दबदबा रहा है। चाहे कांग्रेस की सरकार हो या भाजपा की। मालवा निमाड़ से चुने गए सांसदों को मंत्री पद मिला है। कांग्रेस सांसद रहे प्रकाशचंद्र सेठी वर्ष 1971 की कांग्रेस सरकार में मंत्री रहे। वे राज्य मंत्री, इस्पात मंत्री, पेट्रोलियम व रसायन मंत्री व गृह मंत्री तक रह चुके हैं। आठ बार सांसद रही सुमित्रा महाजन लोकसभा स्पीकर के अलावा मानव संसाधन, संचार व पेट्रोलियम मंत्री रह चुकी है। इंदौर निवासी अनिल माधव दवे मोदी सरकार में पर्यावरण, वन व जलवायु मंत्री रहे है। मंत्री रहते उनका निधन हो गया था। निमाड़ की राजनीति में दबदबा रखने वाले सुभाष यादव के बेटे अरुण यादव और झाबुआ से सांसद रहे कांतिलाल भूरिया भी यूपीए सरकार में मंत्री रह चुके हैं।

एमबीए के पेपर लीक मामले में कॉलेज प्रिंसिपल से पूछताछ करेगी पुलिस

इंदौर। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के पेपर लीक मामले में भाजपा नेता अक्षय कांति बम का नाम सामने आने के बाद राजनीति गरमा गई है। अक्षय के कॉलेज आइडिलिक से यह पेपर लीक हुए थे। पुलिस ने इस मामले में कम्प्यूटर ऑपरेटर और दो छात्रों को गिरफ्तार किया है। उनसे पूछताछ की जा रही है। इस बीच कॉलेज की मान्यता रद्द करने की मांग भी जोर पकड़ने लगी है।

छोटी ग्वालटोली थाना प्रभारी उमेश यादव ने बताया कि हम मामले में जांच कर रहे हैं। अब आइडिलिक कॉलेज की प्रिंसिपल से भी पूछताछ करेंगे। आरोपी कम्प्यूटर ऑपरेटर प्रिंसिपल के रूम तक कैसे पहुंच गया इसकी जांच की जाएगी। आइडिलिक कॉलेज के ऑपरेटर दीपक पिता सुरेश सोलंकी निवासी रंगवासा रोड को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उसके साथ दो अन्य छात्रों को पकड़ा गया है। दीपक ने कॉलेज प्रिंसिपल के रूम से पेपर के बंडल की सील लोहे के स्केल से तोड़कर पेपर निकाला और मोबाइल से फोटो खींचकर कॉलेज के एक छात्र को दो हजार रुपए में बेचा था। फिर छात्र ने इसे अपने साथी को वॉट्सऐप पर भेजा। पुलिस ने स्टूडेंट धीरेंद्र नरवरिया और गौरव सिंह को पकड़ा है। ऑपरेटर दीपक ने बताया कि कॉलेज प्रिंसिपल के कक्ष में सीसीटीवी कैमरे नहीं थे। जिस अलमारी में पेपर के बंडल रखे जाते हैं, उसकी चाबी प्रिंसिपल के ड्रॉवर में ही रहती है। शाम को स्टाफ के जाने के बाद उसने बंडल निकाला और स्केल की मदद से सील उचकाकर पेपर निकाला और फिर वापस रख दिया। इससे किसी को पेपर लीक होने का शक नहीं हुआ।

इंदौर के एमवाय अस्पताल में पुरुष रोगियों के लिए सिर्फ 300 बिस्तरों की सुविधा

सिटी चीफ इंदौर।

मध्य प्रदेश के सबसे अधिक जनसंख्या वाले शहर में शासकीय स्वास्थ्य सुविधाओं के विकास के दावे तो किए जाते हैं, लेकिन उनका फोकस महिलाओं और बच्चों पर ही नजर आता है। शहर में पुरुषों की आबादी दस लाख के करीब है, लेकिन महात्मा गांधी स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय के अधीनस्थ एमवाय अस्पताल ही एकमात्र शासकीय अस्पताल है। वहां भी पुरुष रोगियों के उपचार के लिए मात्र 300 बिस्तरों की सुविधा उपलब्ध है। ऐसे में अनेक पुरुषों को मजबूरन निजी अस्पताल में ही इलाज के लिए जाना पड़ता है। उल्लेखनीय है कि जिला अस्पताल में भी पुरुषों के इलाज के लिए 40 बिस्तरों की सुविधा थी, लेकिन अब नहीं है। शहर में इसके अलावा पीसी सेठी, एमटीएच आदि अस्पताल भी हैं, लेकिन वहां सिर्फ महिलाओं और बच्चों के इलाज की सुविधा है। यह व्यवस्था जिम्मेदारों को भी नजर आती है, लेकिन इसके

बाद भी कोई ध्यान नहीं देते हैं। हालांकि जिला अस्पताल में पुरुष वार्ड बनाने की योजना है, लेकिन वर्षों से इसका निर्माण पूरा नहीं हो पाया है। स्वास्थ्य विभाग के बाणगंगा स्थित अस्पताल की प्रभारी सुनीता यादव का कहना है कि हमारे पास स्टाफ की कमी है। साथ ही महिलाओं के प्रसूति के मामले भी बड़ी संख्या में होती है। इस कारण से हम पुरुष रोगियों को भर्ती नहीं कर पाते हैं।

अभी एमवाय में 800 बिस्तर

बता दें कि वर्तमान में एमवाय अस्पताल में 800 बिस्तरों की सुविधा है। इसमें से 300 पुरुषों के लिए और शेष बच्चों और महिलाओं के लिए हैं। अस्पताल में छठी मंजिल पर 120 बिस्तर भी बनकर तैयार हो रहे हैं। इसके बाद यहां बिस्तरों की संख्या 900 से भी अधिक हो जाएगी। वहीं एमजीएम के अधीन सुपर स्पेशिएलिटी अस्पताल में भी पुरुषों के भर्ती होने की सुविधा है, लेकिन इस अस्पताल में आम मरीजों का भर्ती होना आसान नहीं है। इसके कारण हमेशा मरीजों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जानकारी के अनुसार यहां दोपहर तीन बजे के बाद मरीजों को अधिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है।

बायपास से जुड़ेगा बांबे अस्पताल चौराहा, ट्रैफिक जाम से मिलेगी निजात

तुलसीनगर की पुलिया तोड़कर फोरलेन ब्रिज बनाने की तैयारी

सिटी चीफ इंदौर।

इंदौर में आचार संहिता हटने के बाद पुराने प्रोजेक्टों को गति मिलना शुरू हो गई है। एबी रोड को बांबे अस्पताल होते हुए बायपास से जोड़ने वाली सड़क पर नगर निगम ने ब्रिज का निर्माण शुरू कर दिया है। यह ब्रिज तुलसी नगर के समीप बनाया जा रहा है।

पहले यहां छोटी पुलिया बनी हुई थी, जो संकरी थी। इससे यहां यातायात बाधित होता रहता था। पुरानी पुलिया को फिलहाल तोड़ा जा रहा है। यहां नगर निगम फोरलेन ब्रिज बनाएगा। डेढ़ साल पहले ही इंदौर विकास प्राधिकरण ने बांबे अस्पताल से तुलसी नगर तक फोरलेन सड़क बनाई है। अब इस सड़क को बायपास से जोड़ने की योजना है। प्राधिकरण बायपास से एंडवास एकेडमी स्कूल तक छह लेन सड़क बना चुका है, लेकिन खजराना कब्रिस्तान के कारण सड़क तुलसी नगर तक नहीं बन पाई है। प्राधिकरण पहले ही नए कब्रिस्तान के लिए जमीन कमेटी को दे दी थी, लेकिन कमेटी ने पुराने कब्रिस्तान का कब्जा भी

नहीं छोड़ा और वहां पर शव दफनाने का सिलसिला जारी रहा।

कमेटी को देंगे नोटि

प्राधिकरण ने कब्रिस्तान का कब्जा छोड़ने के लिए कमेटी पदाधिकारियों से चर्चा की है। अफसरों ने बताया कि कमेटी को इसके बारे में नोटिस भी दिया जाएगा। तुलसी नगर से एंडवास एकेडमी तक चारलेन सड़क का काम भी जारी है। डेढ़ साल के भीतर बीआरटीएस रोड से बांबे अस्तपताल होते हुए बायपास तक कनेक्टिविटी मिल जाएगी। इस सड़क के बनने से एमआर-10 मार्ग पर ट्रैफिक का दबाव कम हो जाएगा।

तंत्र क्रिया की आशंका, कई कर्मचारी हो सकते हैं शामिल

जिला अस्पताल में कछुए को मारकर दफनाया

सिटी चीफ इंदौर।

इंदौर के जिला अस्पताल में तंत्र क्रिया करने का मामला सामने आया है। दो महीने पहले शिकायत मिली थी की यहां पर कछुए को दफनाया गया है। इसके बाद वन विभाग की टीम ने खुदाई की और कछुए का शव निकाला। विभाग को दो महीने पहले मिली शिकायत में बताया गया था कि तंत्र क्रिया के दौरान कछुए को लाल कपड़े में लपेटकर दफनाया गया है। शिकायत में यह भी बताया गया था कि इसमें जिला अस्पताल के कर्मचारी ही शामिल हैं।

शिकायत के बाद वन विभाग की टीम ने जिला अस्पताल के कर्मचारी शेखर जोशी ड्रेसर ग्रेड-1, अशोक मालवीय वाहन चालक और संजय काकड़े से पूछताछ की। कछुए को दफनाने के मामले में इन्होंने कई अहम जानकारियां दी और बताया कि उन्होंने किस

जगह कछुए को दफनाया है। इसके बाद टीम ने आज जिला अस्पताल पहुंचकर कर्मचारियों द्वारा बताई गई जगह पर फिर से खुदाई की और वहां से कछुआ निकाला। कछुए का पोस्टमार्टम कराया जाएगा और उसकी मौत का खुलासा किया जाएगा। शिकायत के बाद से वन विभाग इस मामले में सक्रिय है। पूरे मामले को तांत्रिक क्रिया का शक मानकर वन विभाग बारीकी से जांच करने में जुटा हुआ है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद वन विभाग आगे की कार्रवाई करेगा।

8 डिग्री लुढ़ककर 32 पर आया शहर का पारा, उमस से लोग हुए परेशान

सिटी चीफ इंदौर।

इंदौर में शुक्रवार आधी रात को शुरू हुआ बारिश का सिलसिला शनिवार सुबह 8 बजे तक चला। यह बारिश अलग-अलग हिस्सों में रुक-रुककर रिमझिम होती रही। इसके बाद दिनभर मौसम ठण्डा ही रहा। इस दौरान तापमान 8 डिग्री लुढ़ककर 32.8 (-6) डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम वैज्ञानिकों ने रात को गरज-चमक के साथ हल्की बारिश के आसार जताए हैं। शुक्रवार को सुबह से मौसम साफ था। फिर तेजी से धूप चढ़ी और दोपहर को तापमान 40 डिग्री तक पहुंच गया। खास बात यह कि चार दिन की राहत के बाद पारा फिर 40 डिग्री पार गया। इस दौरान गर्मी और उमस का खासा असर रहा। फिर बादल छाए और कई हिस्सों में हल्की बारिश शुरू हो गई जो कुछ देर बाद बंद हो गई। इसके बाद भी बादल छाए रहे। मौसम वैज्ञानिक अरुण शर्मा के मुताबिक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, साइक्लोनिक सकुर्लेशन और ट्रफ लाइन गुजरने की वजह से प्रदेश में आंधी और बारिश का दौर चल रहा है जबकि कई हिस्सों में गर्मी का भी असर है। मानसून भी लगातार गति से आगे बढ़ रहा है। ऐसे में इसके मप्र में समय पर पहुंचने की संभावना बनी हुई है। इंदौर में आज भी गरज-चमक के साथ बारिश होगी।

मालवी भाभी को महंगी पड़ा अयोध्या पर विवादित पोस्ट करना

सिटी चीफ इंदौर।

इंदौर में मालवी भाभी के नाम से प्रसिद्ध प्रतीक्षा जैन नय्यर को अयोध्यावासियों के खिलाफ बोलना भारी पड़ा। उन्होंने इंस्टा और फेसबुक पर एक पोस्ट डालकर अयोध्या जाने वाले पर्यटकों से अयोध्यावासियों का बहिष्कार करने की बात कहीं थी। यह बात कांग्रेस को नागवार गुजरी। उन्होंने मालवी भाभी के खिलाफ शिकायत कर एफआईआर दर्ज करने की मांग कर डाली। लोकसभा चुनाव में अयोध्या लोकसभा सीट से भाजपा के उम्मीदवार हार गए है। सोशल मीडिया पर अयोध्या को लेकर कई तरह के मैसेज चल रहे और मीम बन रहे है। इंदौर की सोशल मीडिया इनफ्लुएंसर प्रतीक्षा जैन मालवी भाभी के नाम से प्रसिद्ध है। वे मालवी भाषा में अपनी पोस्ट अपलोड करती हैं। लोकसभा चुनाव परिणाम आने के बाद उन्होंने अयोध्या को लेकर विवादित पोस्ट डाल दी। इसे लेकर वे ट्रोल भी हुई। कई लोगों ने कमेंट कर उनकी इस पोस्ट पर आपत्ति ली। युवा कांग्रेस समन्यवयक अभिजीत पांडे ने कहा कि वोटरों को जनप्रतिनिधि चुनने का संविधान में लोकतांत्रिक अधिकार है। शिकायत के साथ दिए पोस्ट के स्क्रीन शॉट उनके बहिष्कार की मांग कर मालवी भाभी ने शांति भंग करने की कोशिश की है। पांडे ने क्राइम ब्रांच के डीसीपी राजेश दंडोतिया को लिखित शिकायत कर धारा-153,195 और 294 के तहत केस दर्ज करने की मांग की है। ज्ञापन के दौरान युवा कांग्रेस नेता स्वप्निल कांबले, नितिन कुशवाह व अन्य नेता मौजूद थे।

मोटापे के कारण मेडिक्लेम नहीं देने की बीमा कंपनी की दलील खारिज

सिटी चीफ इंदौर।

63 साल के वृद्ध का ढाई लाख रुपए का मेडिक्लेम खारिज करने की बीमा कंपनी की दलील को उपभोक्ता फोरम ने खारिज कर दिया। यह पॉलिसी 20 साल पहले ली गई थी। बीमा कंपनी ने मेडिक्लेम यह कहते हुए नहीं दिया था कि इलाज मोटापा कम करने का कराया गया है। यह पॉलिसी के दायरे में नहीं है।

इसी के खिलाफ वृद्ध ने उपभोक्ता फोरम की शरण ली। यहां बीमा कंपनी के तर्क नहीं चले और उसे इलाज में खर्च हुए ढाई लाख रुपए चुकाने के आदेश दिए हैं। आदेश 28 मई को किया गया, जिसकी डिटेल कॉपी अब सामने आई है। मामला राधा नगर, नीलकंठ कॉलोनी के रहने वाले राजेंद्र भाटिया का है। साल 2000 में उन्होंने खुद व परिवार का नेशनल इंश्योरेंस कंपनी से मेडिक्लेम कराया था। 16 दिसंबर 2020 को पैरों में सूजन आई। सांस लेने में भी दिक्कत हुई। इंदौर के ही प्राइवेट अस्पताल में चेकअप कराया। सीटी स्कैन और अन्य जांचें हुईं।

डॉक्टर की सलाह के बाद मुंबई ले गए और वहां भी एक प्राइवेट अस्पताल में

चेकअप कराया, जिसके बाद वहां भर्ती करना पड़ा। जांच में खुलासा हुआ कि उनके फेफड़ों में पानी भर गया है। मुंबई के प्राइवेट अस्पताल में भाटिया को करीब 10 दिन भर्ती रखा। यहां शरीर से पानी निकाला गया तब राहत मिली। इलाज में 2.33 लाख रुपए खर्च आया। बीमा कंपनी ने 9 अगस्त 2021 को यह कहकर क्लेम देने से मना कर दिया कि मोटापे की वजह से मेडिक्लेम देने के लिए बाध्य नहीं है। हालांकि, भाटिया ने जानकारी दी कि बीमा कंपनी ने 2000 में मेडिक्लेम पॉलिसी करते समय वजन संबंधी कोई जानकारी नहीं ली थी। जब 2020 से 2021 के लिए 5 लाख रुपए की यह पॉलिसी रिन्यू कराई थी तब भी ऐसी कोई जानकारी नहीं ली गई।

बीमा कंपनी ने यह दिया तर्क

बीमा कंपनी पैनल ने इलाज के दस्तावेज के आधार पर भाटिया को यह तर्क दिया कि हाइपोवेंटिलेशन के साथ ऑब्स्ट्रक्ट स्लीम एपनिया के साथ पिकविकियन सिंड्रोम से ग्रस्त थे। इसे ओबेसिटी हाइपोवेंटिलेशन सिंड्रोम कहा जाता है जो मोटापे के कारण होता है। ऐसे में उन्हें मेडिक्लेम का लाभ नहीं दिया जा सकता। बीमा कंपनी द्वारा मेडिक्लेम खारिज करने के बाद भाटिया ने जिला उपभोक्ता फोरम की शरण ली। यहां करीब एक साल सुनवाई चली। भाटिया का कहना है कि बीमा कंपनी की बड़ी अजीबो-गरीब स्थिति बताई है। 2000 में जब मेडिक्लेम पॉलिसी ली तब मेरा वजन करीब 100 किलो था। उस दौरान कंपनी ने वजन को लेकर कोई जानकारी नहीं ली, न ही आपत्ति ली गई। 2020 में जब बीमार हुआ और क्लेम रिजेक्ट हो गया तब मेरा वजन पहले से कम था। इसके बाद मोटापा कारण बताकर क्लेम खारिज कर दिया गया था।

बीमा कंपनी को चुकाना होंगे 2.33 लाख

एडवोकेट रविराज सिंह के मुताबिक बीमा कंपनी ने जो दस्तावेज पेश किए उसमें कोई भी ऐसा तथ्य रिकॉर्ड पर नहीं पाया गया जिससे यह साबित हो कि फरियादी ने मोटापे का ट्रीटमेंट कराया है।

इसके बावजूद बिना ठोस कारण के क्लेम खारिज किया है। बीमा कंपनी को 2 लाख 33 हजार 550 रुपए रुपए चुकाने होंगे। साथ में क्लेम पेश करने की तारीख 4 जनवरी 2023 से 9त्न ब्याज सहित राशि 45 दिन के अंदर देनी होगी। मानसिक परेशानी के लिए 10 हजार रुपए और परिवाद खर्च 5 हजार रुपए भी लगेगा।

भोपाल-प्रयागराज उड़ान में आई तकनीकी खराबी, साढ़े चार घंटे बाद हुई टेकआफ

सिटी चीफ भोपाल।

भोपाल। राजा भोज एयरपोर्ट पर भोपाल से प्रयागराज जा रही इंडिगो की उड़ान में शनिवार को टेकआफ होते समय अचानक तकनीकी खराबी आ गई। उड़ान समय पर टेकआफ नहीं हो सकी। यात्रियों को परेशान होना पड़ा। रायपुर उड़ान भी साढ़े तीन घंटे की देरी से पहुंची। प्रयागराज उड़ान हैदराबाद से भोपाल आने के बाद प्रयागराज रवाना होती है। शनिवार को हैदराबाद से तो समय पर विमान आ गया लेकिन यही उड़ान जब प्रयागराज जा रही थी तो इसमें तकनीकी खराबी आ गई। उड़ान संख्या 6-ई 7926 की खराबी को तत्काल ठीक नहीं किया जा सका। प्रयागराज जा रहे कुछ यात्रियों को वाया दिल्ली रवाना किया गया। कुछ यात्रियों ने रिफंड ले लिया। उड़ान में कुल 65 यात्री प्रयागराज जाने वाले थे।

Demo Pic

इंडिगो के इंजीनियरों ने दोपहर को विमान की खराबी ठीक कर ली। उड़ान निर्धारित समय से साढ़े चार घंटे विलंब से दोपहर ढाई बजे प्रयागराज के लिए टेकआफ हुई। करीब 50 यात्री इस उड़ान से रवाना हुए। एयरपोर्ट डायरेक्टर रामजी अवस्थी के अनुसार तकनीकी कारणों से उड़ान समय पर टेकआफ नहीं हो सकी थी।

इधर, रायपुर से भोपाल आने वाली उड़ान संख्या 6-ई 7371 भी मौसम की खराबी के कारण निर्धारित समय शाम 5.10 बजे के बजाय रात्रि 8.45 राजा भोज एयरपोर्ट पर लैंड हुई। उल्लेखनीय है कि गर्मी एवं मौसम की खराबी के कारण इस माह कई बार उड़ानें लेट हुई हैं।

प्रतिष्ठानों के खाद्य लाइसेंस निलंबित कर जांच में लिए प्रकरण

रेलवे स्टेशन पर बेचे जा रहे थे गंदगी में बने चाय-समोसे

सिटी चीफ भोपाल।

भोपाल। शहर में होटल, रेस्टोरेंट संचालकों द्वारा अधिक मुनाफा कमाने के चक्कर में लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। कभी मिठाई में कीड़े, खाने में काकरोच, इल्ली आदि निकलने के मामले सामने आते हैं तो वहीं जहां खाद्य पदार्थ बनाया जाता है वहां गंदगी का अंबार लगा रहता है। खाद्य सुरक्षा प्रशासन अमले ने ऐसे प्रतिष्ठानों पर छापामार कार्रवाई की है जहां पर भारी गंदगी के बीच चाय, समोसे बनाकर रेल यात्रियों को बेचकर उनकी सेहत से खिलवाड़ किया जा रहा था। रेल और खाद्य अमले ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए प्रतिष्ठान का खाद्य लाइसेंस निलंबित करते हुए प्रकरण जांच में ले लिया है। जानकारी के अनुसार रेलवे मंडल सुरक्षा बल, रेलवे वाणिज्य विभाग के साथ खाद्य सुरक्षा प्रशासन अमले द्वारा शुक्रवार को भोपाल रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म और ट्रेनों में बेचे जाने वाले समोसे, चाय आदि के निर्माण स्थलों का निरीक्षण किया गया। इस दौरान सिकंदरी सराय स्थित अमोली इंटरप्राइजेज में भारी गंदगी के बीच समोसे बनाए जा रहे थे। इससे तत्काल प्रतिष्ठान का खाद्य लाइसेंस निलंबित किया गया। वहीं थाना बजरिया शंकराचार्य नगर के सामने संचालित दीपू समोसा सेंटर (इदरीस समोसा) में भी गंदगी के बीच समोसे बनाए जा रहे थे। कारोबारी के पास खाद्य लाइसेंस भी नहीं था। इससे कार्रवाई करते हुए खाद्य कारोबार को बंद काया गया है।

गंदगी के बीच बनाई जा रही थी चाय

सिकंदरी सराय स्थित न्यू विजय होटल के एक कमरे में एक प्रतिष्ठित चाय निमार्ता संस्थान के द्वारा अत्यंत गंदगी के बीच चाय बनाई जा रही थी। यहां बनी हुई चाय ट्रेनों और रेलवे स्टेशन यात्रियों को बेची जा रही थी।मौके पर संस्थान के कर्मचारी एवं जिम्मेदार व्यक्ति के मौके पर उपस्थित नहीं होने के कारण प्रकरण जांच में लिया गया है।मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी देवेंद्र दुबे ने बताया कि विश्व खाद्य दिवस के मौके पर गंदगी में चाय, समोसा बनाने वाले प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई की गई है। एक प्रतिष्ठान के बारे में दस्तावेज भवन स्वामी से मांगे गए हैं। इसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।

2 करोड़ रुपए मांगने वाली महिला गिरफ्तार, रीवा की रहने वाली है आरोपी, कई और लोग भी दर्ज करा चुके हैं शिकायत

हनी ट्रैप में फंसे मंत्री के पूर्व ओएसडी

सिटी चीफ भोपाल।

भोपाल। एक महिला द्वारा मंत्री के तत्कालीन ओएसडी को दुष्कर्म के झूठे केस (हनी ट्रैप) में फंसाने की धमकी देकर दो करोड़ रुपए मांगने वाली महिला को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वह लगभग एक वर्ष से अधिकारी को परेशान कर रही थी। मांग पूरी नहीं होने पर उसने कांट-छांट कर तैयार किया अश्लील वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित कर बदनाम करने की भी बात कही थी। शिकायत की जांच के बाद हबीबगंज पुलिस ने आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया है। वह मूलतः रीवा की रहने वाली है। उसके खिलाफ कई और लोगों ने भी शिकायत कर रखी है। हबीबगंज थाना पुलिस के मुताबिक डा. जीवन रजक प्रदेश के जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट के ओएसडी के तौर पर पदस्थ रहे हैं। जुलाई 2023 में एक महिला ने मंत्री के बंगले पर पहुंचना शुरू किया था। खुद को पत्रकार बताने वाली महिला ओएसडी डा. रजक से बातचीत करने लगी। वह अक्सर कुछ लोगों के काम कराने की सिफारिश लेकर पहुंचती थी। ट्रांसफर, पोस्टिंग के काम में डा. रजक ने मदद करने से मना कर दिया, तो

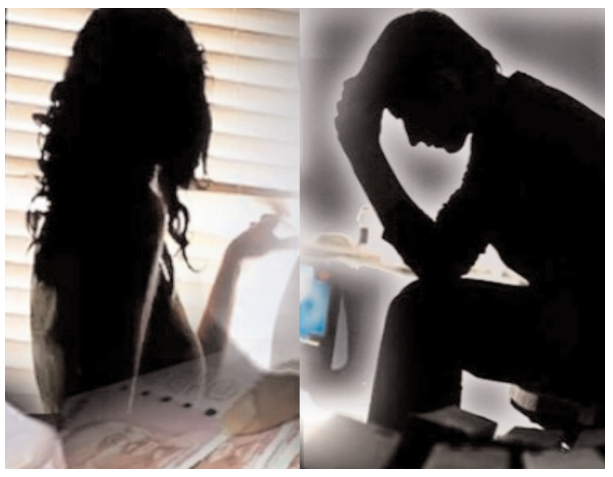

उसने उन्हें धमकाना शुरू कर दिया था। वह करीब एक वर्ष से डा. रजक को उसके मनमाफिक काम नहीं करने पर दुष्कर्म के झूठे मामले में फंसाने की धमकी दे रही थी।

घर पहुंचकर दिखाया बदनामी का डर

डा. रजक किसी भी तरह के सिफारिशी काम करने में मदद करने से साफ मना कर दिया, तो पिछले दिनों महिला शिवाजी नगर स्थित उनके घर जा धमकी। बातचीत करने के दौरान उसने धमकी दी कि यदि उसे दो करोड़ रुपये नहीं दिए, तो वह उनका काट-छांटकर तैयार किया अश्लील वीडियो प्रसारित कर देगी। इससे उनकी बदनामी होगी। जेल भी जाना पड़ सकता है। मानसिक रूप से बुरी तरह परेशान होने पर डा. रजक ने घटना की लिखित शिकायत थाने में की थी। साथ ही महिला द्वारा समय-समय पर उन्हें धमकाने संबंधी साक्ष्य भी संलग्न किए थे। जांच के बाद पुलिस ने शुक्रवार को महिला के खिलाफ ब्लैकमेल करने का केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया। जांच में पता चला कि महिला के खिलाफ रीवा पुलिस में भी कई शिकायत दर्ज हैं। उससे परेशान होकर कई लोग अदालत में निजी शिकायत कर चुके हैं।

परियोजना अथॉरिटी ने मप्र-उप्र और केंद्र सरकार के अधिकारियों के साथ मिलकर पूरी की प्रक्रिया, केंद्र की नई सरकार करेगी शिलान्यास

जुलाई में शुरू होगा केन-बेतवा लिंक परियोजना का काम

सिटी चीफ भोपाल।

भोपाल। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की बहुप्रतीक्षित केन-बेतवा लिंक परियोजना का शिलान्यास अब केंद्र की नई सरकार द्वारा किया जाएगा। इसको लेकर तैयारी शुरू हो गई है। जुलाई में परियोजना का शिलान्यास करने की कार्ययोजना बनाई जा रही है। इसके अंतर्गत बनने वाले दोधन बांध के लिए तकनीकी निविदा पूरी हो गई है। दोधन बांध की ऊंचाई 15 मीटर से अधिक होगी। आचार संहिता खत्म होने के बाद कंपनी का चयन होगा।

निविदा में अडानी, दिलीप बिल्डकान, हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी (एचसीसी), एस्कान इंफ्रास्ट्रक्चर (इंडिया) लिमिटेड, एसटीएन सहित 22 कंपनियों ने रुचि दिखाई है। कुल 44 हजार 605 करोड़ रुपये की इस परियोजना को पूरा करने में छह वर्ष लगेंगे। इससे उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में साढ़े आठ लाख हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई क्षमता का विकास होगा तो लाखों लोगों को पेयजल की सुविधा मिलेगी। केन-बेतवा लिंक परियोजना अथारिटी के भोपाल स्थित कार्यालय ने मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और केंद्र सरकार के अधिकारियों के साथ मिलकर परियोजना की प्रक्रिया पूरी कर ली है। बता दें, केन-बेतवा लिंक परियोजना को लेकर मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच वर्ष 2005 में अनुबंध हुआ

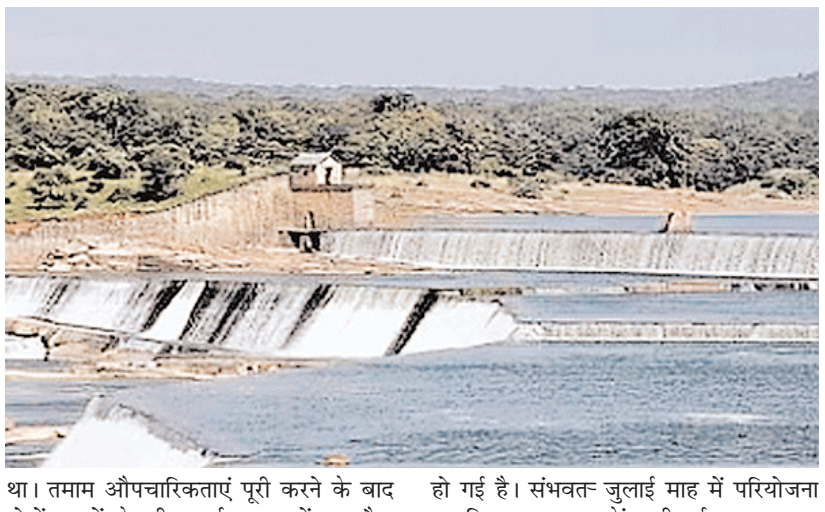

था। तमाम औपचारिकताएं पूरी करने के बाद दोनों राज्यों के बीच वर्ष 2021 में समझौता हुआ। इस परियोजना में केंद्र सरकार 90 प्रतिशत राशि देगी। दोनों राज्य सरकारों को कुल लागत की पांच-पांच प्रतिशत राशि देनी होगी। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की बहुप्रतीक्षित केन-बेतवा लिंक परियोजना के लिए केंद्र सरकार ने 45 हजार करोड़ रुपए जारी कर दिए हैं। केंद्र सरकार से लागत की 90 प्रतिशत राशि मिलने के बाद अब दोनों राज्य सरकारों को बकाया पांच-पांच प्रतिशत राशि देनी होगी। इसी के साथ परियोजना के मैदानी काम को शुरू करने की तैयारी भी तेज हो गई है। संभवतः जुलाई माह में परियोजना का शिलान्यास अब केंद्र की नई सरकार द्वारा किया जाएगा। इस परियोजना से दोनों ही राज्य के बुंदेलखंड क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा मिलेगी। इससे किसानों की आय बढ़ेगी। परियोजना के अंतर्गत बनने वाले दोधन बांध के लिए तकनीकी निविदा पूरी हो गई है। दोधन बांध की ऊंचाई 15 मीटर से अधिक होगी। दोधन बांध को पूरा करने में छह वर्ष लगेंगे। इससे उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में साढ़े आठ लाख हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई क्षमता का विकास होगा तो लाखों लोगों को पेयजल की सुविधा मिलेगी।

अस्पताल में 22 चिकित्सक के बजाय रह गए 15, स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित

बैरागढ़ सिविल अस्पताल में रेडियोलॉजिस्ट ही नहीं

सिटी चीफ भोपाल।

भोपाल। संत हिरदाराम नगर एवं आसपास के ग्रामीण इलाकों की करीब दो लाख आबादी बैरागढ़ सिविल अस्पताल पर निर्भर है इसके बावजूद अस्पताल में लंबे समय से रेडियोलाजिस्ट का पद खाली है। प्रसूती के लिए आई महिलाओं को सोनोग्राफी के लिए परेशान होना पड़ता है। मेडीकल आफिसर के दो पद भी खाली हैं। अस्पताल में लंबे समय से चिकित्सकों की कमी महसूस की जा रही थी। अस्पताल पर बैरागढ़ के अलावा आसपास के ग्रामीण जनता के स्वास्थ्य का भार है। एक समय अस्पताल में 22 चिकित्सक हुआ करते थे। अब यह संख्या घटकर 15 रह गइ है। चिकित्सकों की कमी के कारण स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हो रही थीं। अस्पताल

प्रबंधन ने कई बार इस संबंध में विभागीय स्तर पर पत्राचार किया। हाल ही में एनेस्थेशिया एवं पैथालाजिस्ट की नियुक्ति की गई है लेकिन चिकित्सकों की कमी महसूस की जा रही है। सोनोग्राफी के लिए सप्ताह में दो दिन बाहर के चिकित्सक आते हैं। अस्पताल में हर माह 300 से अधिक सोनोग्राफी जांच होती है, इसके बावजूद रेडियोलाजिस्ट नहीं है।

मेटरनिटी विंग के लिए डॉक्टर नहीं

अस्पताल में मेटरनिटी विंग का काम अंतिम चरण में है। इसका निर्माण होने से महिलाओं को सुविधा हो जाएगी। इसके साथ ही आधुनिक आपरेशन थियेटर एवं लेबर रूम का निर्माण किया जाएगा। 45 बिस्तर वाला पीएनसी वार्ड एवं आठ बिस्तर वाला आइसोलेशन वार्ड बनाया जा रहा है। नए विंग में गर्भवती महिलाओं के इलाज की विशेष व्यवस्था रहेगी। बर्न यूनिट एवं बच्चों के लिए अलग वार्ड भी बन रहा है पर इसके लिए चिकित्सकों की पदस्थापना अभी तक नहीं की जा सकी है। जब तक चिकित्सक तैनात नहीं होते तब तक इसका लाभ मरीजों को नहीं मिल सकेगा।

कुछ चिकित्सकों की कमी है

अस्पताल में मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए मेडीकल आफिसर की कमी है। रेडियोलाजिस्ट नहीं है लेकिन सोनोग्राफी के लिए सप्ताह में दो दिन तय हैं। महिला मरीजों को परेशानी नहीं होने दी जाती। डाक्टरों की संख्या बढ़ाने के लिए विभागीय स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं।

प्रदेश में मानसून आने की संभावित तारीख 16 जून, इस बार 12 जून तक कर सकता है प्रवेश

5 सालों में तीसरी बार तय समय से पहले मानसून आने के संकेत

सिटी चीफ भोपाल।

भोपाल। गर्मी का सामना कर रहे लोगों के लिए अच्छी खबर है। केरल में नियत समय से दो दिन पहले पहुंचा दक्षिण-पश्चिम मानसून लगातार आगे बढ़ रहा है। अभी तक मानसून केरल, कर्नाटक के अलावा आंध्र प्रदेश के अधिकांश हिस्से में और तेलंगाना, महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में पहुंच चुका है। वर्तमान में उसकी उत्तरी सीमा रत्नागिरी, सोलापुर, मेडक, भद्राचलम, विजय नगर और इस्लामपुर से होकर गुजर रही है। मौसम विज्ञानियों के अनुसार इस बार बंगाल की खाड़ी से अधिक सक्रियता अरब सागर में दिखाई दे रही है। मानसून के रविवार-सोमवार तक मुंबई पहुंचने की संभावना है।

मौजूदा स्थिति को देखते हुए इस बार मानसून 12 जून तक मध्य प्रदेश में प्रवेश कर सकता है।

प्रदेश में मानसून आने की संभावित तारीख 16 जून है। पिछले पांच वर्ष में तीसरी बार मानसून के तय तारीख से पहले आने के संकेत मिल रहे हैं। मौसम विज्ञान केंद्र के पूर्व वरिष्ठ मौसम विज्ञानी अजय शुक्ला ने बताया कि केरल पहुंचने के बाद मानसून की गतिविधियां बंगाल की खाड़ी में तो थमी हुई हैं, लेकिन अरब सागर की तरफ से काफी अच्छी प्रगति जारी है। दो-तीन दिन के भीतर मानसून मुंबई के साथ ही दक्षिणी छत्तीसगढ़ में भी प्रवेश कर सकता है। इस वजह से मानसून के मध्य प्रदेश में 12 जून तक पहुंचने की पूरी संभावना दिख रही है। बता दें कि पहले मध्य प्रदेश में मानसून आने की संभावित तिथि 13 जून थी, लेकिन वर्ष 2019 में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने उसे बढ़ाकर 16 जून तय कर दिया।

कल भेल बरखेड़ा महात्मा गांधी शासकीय स्कूल के सामने लगेगा स्वास्थ्य शिविर, स्वास्थ्य जांच के बाद मिलेगी यात्रा की अनुमति। पहले जत्थे में जाएंगे 300 श्रद्धालु।

भोपाल से 26 जून को होगा रवाना अमरनाथ यात्रियों का पहला जत्था

सिटी चीफ भोपाल।

भोपाल। राजधानी भोपाल से अमरनाथ यात्रा करने के लिए श्रद्धालुओं का पहला जत्था 26 जून को रवाना होगा। इसमें 300 यात्री शामिल होंगे। ओम शिव शक्ति सेवा मंडल के नेतृत्व में पहले जत्थे में शामिल सभी यात्रियों का भोपाल रेलवे स्टेशन पर फूल माला पहनाकर स्वागत किया जाएगा। यात्री 29 जून से शुरू हो रही अमरनाथ यात्रा करेंगे। इसके लिए नौ जून रविवार को भेल बरखेड़ा स्थित शासकीय महात्मा गांधी स्कूल के सामने स्वास्थ्य शिविर लगाया जाएगा। इसमें अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले सभी यात्रियों का एक-एक करके डाक्टरों की टीम स्वास्थ्य परीक्षण करेगी। जांच में सही मिले लोगों को यात्रा पर जाने की अनुमति दी जाएगी।

ओम शिवशक्ति सेवा मंडल की ओर से अमरनाथ यात्रा पर भेजने के लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मंडल के सचिव रिंकू भटेजा ने बताया कि यात्रा संबंधी मार्ग, कठिनाइयां सहित अन्य बातें बताई गई हैं, ताकि यात्रा करने वाले लोगों को परेशानी न हो और बफार्नी बाबा के दर्शन आसानी से हो सकें। मंडल के पदाधिकारी भी जत्थे के साथ जाएंगे, जिन्हें अमरनाथ यात्रा करने का वर्षों से अनुभव है। इस बार अमरनाथ यात्रा के लिए पंजीयन कराने वालों की संख्या में 15 हजार से अधिक पहुंच गई है। आनलाइन व

आफलाइन पंजीयन 15 हजार हो चुके हैं। ये यात्री अलग-अलग तारीख पर यात्रा करेंगे। मंडल की ओर से 29 जून से 19 अगस्त तक चलने वाली अमरनाथ यात्रा के लिए 15 जत्थे रवाना किए जाएंगे। इनमें 300, 200, 100 यात्रियों के जत्थे शामिल होंगे। इसके अलावा अन्य यात्री भी अपने हिसाब से अमरनाथ यात्रा पर जाएंगे।

बदली यात्रियों के लिए ठहरने की व्यवस्था

ओम शिव सेवा मंडल की ओर से जम्मू में संत रविदास मंदिर प्रांगण में यात्रियों के लिए ठहरने व भोजन की व्यवस्था हर वर्ष की जाती थी। इस बार जम्मू में लगने वाले भंडारा बालटाल व चंदनवाड़ी में शिफ्ट किया गया है। वहीं यात्रियों को रात्रि में विश्राम जम्मू स्टेशन के पास वैष्णवी धाम व कालिका धाम में कराया जाएगा। इस दौरान मंडल के पदाधिकारी यात्रियों की व्यवस्था में मौजूद रहेंगे।

साम्पदकीय

दिल्ली जल संकट पर न हो राजनीति

जिस समस्या को सुलझाने के लिये शासन-प्रशासन को सजग होना चाहिए था, उसको लेकर शीर्ष अदालत को निर्देश देने पड़ रहे हैं। कोर्ट ने दो राज्यों की सरकारों को निर्देश दिए हैं कि दिल्ली के लिये अतिरिक्त पानी का सुचारू प्रवाह सुनिश्चित हो। निस्संदेह, गर्मी के मौसम में जीवनदायी पानी को लेकर राजनीति तो नहीं ही होनी चाहिए।

यह विडंबना ही है कि भीषण गर्मी में देश की राजधानी में जल संकट को सुलझाने के बजाय राजनीतिक बयानबाजी की जा रही है। जिस समस्या को सुलझाने के लिये शासन-प्रशासन को सजग होना चाहिए था, उसको लेकर शीर्ष अदालत को निर्देश देने पड़ रहे हैं। कोर्ट ने दो राज्यों की सरकारों को निर्देश दिए हैं कि दिल्ली के लिये अतिरिक्त पानी का सुचारू प्रवाह सुनिश्चित हो। निस्संदेह, गर्मी के मौसम में जीवनदायी पानी को लेकर राजनीति तो नहीं ही होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सरकार से कहा है कि हिमाचल प्रदेश जिस 137 क्यूसेक अतिरिक्त पानी को दिल्ली हेतु छोड़ने के लिये राजी हुआ, उसका दिल्ली तक पहुंचना सुनिश्चित करे। वैसे तो देश के कई राज्यों में नदियों के जल बंटवारे को लेकर लंबे समय से विवाद जारी हैं, विवाद सुलझाने को कई प्राधिकरण भी बने हैं, लेकिन कम से कम पेयजल संकट के दौरान राजनीति नहीं की जानी चाहिए। एक तथ्य यह भी कि अतिरिक्त पानी देने वाले हिमाचल की सीमा दिल्ली से नहीं लगती, इसलिए हरियाणा के वजीराबाद बैराज के माध्यम से दिल्ली को अतिरिक्त पानी भेजा जा सकता है। बहरहाल, जानलेवा गर्मी के बीच दिल्ली जल संकट को दूर करने के लिये अदालत के हस्तक्षेप के बाद राज्यों में सहयोग तथा जल संसाधनों के तर्कसंगत प्रबंधन की जरूरत महसूस की जा रही है। दरअसल, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आबादी के लगातार बढ़ते दबाव के बीच जल संकट हर साल गर्मियों में गहरा जाता है। राष्ट्रीय राजधानी अपनी जल आपूर्ति के लिये पड़ोसी राज्यों पर ही निर्भर रही है। जिसके मूल में जल प्रबंधन में संवेदनहीनता व अक्षमता भी उजागर होती है। दिल्ली सरकार भी सारे साल प्रयास करने के बजाय सिर्फ गर्मियों में संकट पैदा होने पर हाथ-पांव मारती नजर आती है। दरअसल, दिल्ली सरकार अकसर कहती है कि कारगर तंत्र के अभाव में राज्य को न्यायसंगत ढंग से पानी की आपूर्ति नहीं हो पाती है। जिसके मूल में जलप्रबंधन में प्रणालीगत अंतर्विरोध भी निहित हैं।

वहीं दूसरी ओर हरियाणा अकसर अपनी पानी की जरूरतों तथा हिमाचल प्रदेश से अतिरिक्त जल आपूर्ति मापने के लिये स्पष्ट तंत्र की कमी की बात कहता रहा है। दिल्ली सरकार कहती है कि हरियाणा उसके हिस्से का पानी नहीं पहुंचने देता है। दरअसल, जब दिल्ली व हरियाणा में अलग-अलग राजनीतिक दलों की सरकारें होती हैं तो जल संकट को लेकर आरोप-प्रत्यारोप की राजनीति शुरू हो जाती है। दूसरी ओर, इस विवाद में मध्यस्थता करने के लिये बने ऊपरी यमुना नदी बोर्ड की कार्यक्षमता को लेकर भी सवाल उठाये जाते रहे हैं। दरअसल, जरूरत इस बात की है कि नदी बोर्ड जल प्रबंधन के लिए सबके सहयोग से पारदर्शी दृष्टिकोण अपनाया जाए। निस्संदेह, गर्मी के मौसम में पर्याप्त पानी न मिलना जन स्वास्थ्य के लिये भी खतरा है। जिसके लिये जल प्रबंधन स्थायी और न्यायसंगत ढंग से करने की आवश्यकता महसूस की जा रही है। दिल्ली सरकार की शिकायत पर जहां सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल सरकार को अतिरिक्त पानी देने तथा हरियाणा सरकार को जल प्रवाह बाधा मुक्त बनाने को कहा है, वहीं दिल्ली के लोगों से कहा है कि वे पानी की बबार्दी रोकें। साथ ही जल प्रबंधन से जुड़ी अक्षमताओं को दूर करने को कहा गया है। जिसमें जल रिसाव व चोरी रोकने तथा टैंकर माफिया की निरंकुशता पर भी अंकुश लगाने की जरूरत है। वहीं अवैध कनेक्शनों पर भी नकेल कसने की जरूरत बतायी है। दूसरी ओर जरूरी है कि राज्यों में बेहतर सहयोग के लिए यूवाईआरबी जैसे निकाय इस बाबत हुए समझौतों का क्रियान्वयन सुनिश्चित करें। स्पष्ट है कि जल प्रबंधन को लेकर दृष्टिकोण राजनीति से मुक्त तथा सहयोगात्मक होना चाहिए। जो नागरिकों की जरूरतों के लिये प्राथमिकता का मार्ग सुनिश्चित करे। दिल्ली से देश की प्रतिष्ठा जुड़ी है और देश के नीति-नियंताओं के साथ ही तमाम विदेशी दूतावास वहां सक्रिय हैं। दिल्ली में पानी संकट होने से पूरी दुनिया में भारत को लेकर अच्छा संदेश नहीं जाएगा। भविष्य में ऐसे संकटों को रोकने और कुदरत के इस बहुमूल्य संसाधन के समान वितरण को सुनिश्चित करने के लिये एक आदर्श पहल होनी चाहिए।

रुरु की मृत पत्नी कैसे हुई पुनर्जीवित, संस्कृति के पन्नों से जानें पूरी कहानी

नेता प्रतिपक्ष के लिए कितनी सीटों की जरूरत है यह सवाल बेहद अहम रहा है? इस बार कांग्रेस को करीब 100 सीटें मिली है। इस बार नेता प्रतिपक्ष का पद लोकसभा में कांग्रेस के संसदीय दल के नेता को मिलेगा। पिछले दो लोकसभा में कांग्रेस 55 सीटों से पीछे रह गई थी और इस कारण उन्हें नेता प्रतिपक्ष का दर्जा नहीं मिल पाया था। नेता प्रतिपक्ष के लिए कुल सीटों की संख्या का 10 फीसदी नंबर का नियम कहां से आया और इसको लेकर कानूनी पेंचीदगियां क्या है इस पर भी बहस है। नेता प्रतिपक्ष को लेकर कानूनी जानकार और लोकसभा में पूर्व सेक्रेटरी जनरल पीडीटी अचारी की राय अलग है। उनका कहना है कि सरकार के विरोधी दलों में सबसे बड़ी पार्टी के नेता को विरोधी दल के नेता का दर्जा मिलता है। इस बारे में हालांकि यह बात चलन में है कि नेता प्रतिपक्ष बनने के लिए सबसे बड़े विरोधी दल को कम से कम कुल सीटों का 10 फीसदी यानी 55 सीटें चाहिए। लेकिन लोकसभा के पूर्व सेक्रेटरी जनरल अचारी इसकी अनिवार्यता नहीं मानते है। उनके मुताबिक संसदीय एक्ट 1977 में नेता प्रतिपक्ष के वेतन भत्ते आदि को परिभाषित किया गया है। एक्ट की धारा-2 में नेता प्रतिपक्ष को परिभाषित किया गया है। इसके तहत कहा गया है कि नेता प्रतिपक्ष विरोधी दल का नेता होता है और लोकसभा में जिस विपक्षी दल की संख्या सबसे ज्यादा होती है उसके नेता को नेता प्रतिपक्ष के तौर पर लोकसभा के स्पीकर मान्यता देते हैं। इस एक्ट में कहीं नहीं लिखा हुआ है कि नेता प्रतिपक्ष के लिए कुल सीटों की संख्या का 10 फीसदी यानी 55 सीटें होनी चाहिए। दरअसल नेता प्रतिपक्ष के मामले में यह चलन हो गया है कि कुल सीटों की संख्या का 10 फीसदी होना चाहिए। अचारी बताते हैं कि पहले आम चुनाव के बाद स्पीकर ने गाइडलाइंस बनाई थी और कहा था कि नेता प्रतिपक्ष के लिए 10 फीसदी संख्या होना चाहिए और यह कोरम के बराबर मान लिया गया था। कोरम के लिए भी 10 फीसदी नंबर होना चाहिए। 1977 के एक्ट के बाद जो परिभाषा तय हुई उसमें इसकी अनिवार्यता नहीं रही लेकिन फिर भी यह चलन में है और 10 फीसदी सीटें नहीं मिलने के कारण पिछले दो लोकसभा कार्यकाल में कांग्रेस को लोकसभा में उनके नेता को नेता प्रतिपक्ष का दर्जा नहीं मिल पाया था। नेता प्रतिपक्ष का मामला बेहद पुराना है। 1952 में पहले आम चुनाव के बाद लोकसभा का गठन हुआ और तब 10 फीसदी सीटें मिलने के बाद नेता प्रतिपक्ष का दर्जा दिए जाने का नियम आया था। इसके लिए तत्कालीन लोकसभा अध्यक्ष जी वी मावलंकर ने ऑर्डर नंबर 120-123 के तहत नियम तय किया था कि नेता प्रतिपक्ष के लिए 10 फीसदी सीटें चाहए। लेकिन इसके बाद 1977 में जब कानून बनाया गया तब उक्त निर्देश की अहमियत नहीं रह गई। 1977 में नेता प्रतिपक्ष वेतन भत्ता कानून पारित किया गया था। इसमें कहा गया कि सरकार के विरोधी दल का नेता उसे माना जाएगा जिसकी संख्या सबसे ज्यादा होगी।

जनादेश का सम्मान करे सियासत

लोकतंत्र के पर्व में शिकस्त व जीत का सिलसिला जारी रहेगा, मगर अहम पहलू यह है कि लोकतंत्र में लोगों का भरोसा कायम रहना चाहिए। देश की सियासत को जनता का जनादेश पूरी अकीदत से स्वीकार करना होगा।

मौजूदा वक्त में मुल्क की सियासत जश्न-ए-मसर्रत में मसरूर है। देश की फिजाओं में भी सियासी तरन्नुम की धुन महसूस की जा सकती है। देश के करोड़ों मतदाताओं ने अपने बेशकीमती वोट की ताकत से मैदान-ए-सियासत में किस्मत आजमा रहे सियासी रहनुमाओं को जम्हूरियत की सबसे बड़ी पंचायत में पहुंचा कर लोकतंत्र की मजबूती का एक और सुनहरा मजमून लिख दिया। सियासत के कई मुनाजिर सियासी बज्म में चुनावी जीत का श्रेय लेने में लगे हैं, जबकि लोकतंत्र में जनता का जनादेश सर्वोपरि है। हैरत यह भी है कि मतदाताओं ने अलगाववाद की हिमायत करने वाले कुछ सियासी रहनुमाओं को भी देश की संसद में भेज दिया है। चुनावी रैलियों से लेकर जंनसम्पर्क व रोड शो तथा सोशल मीडिया तक चुनावों का प्रचार हुआ। सियासी दलों की प्रतिष्ठा का सवाल बन चुके चुनावों में सियासी विरासत को बचाने की जद्दोजहद भी जारी थी, मगर मतदाताओं के खामोश फैसले ने देश की सियासत को चौंका दिया है। एग्जिट पोल को लेकर सियासत के ज्योतिषाचार्यों के दावे धराशायी हो गए। हालांकि देश में एक बार फिर गठबंधन की सियासत का दौर शुरू हो गया है। कहर बरपाती गर्मी के बीच लोगों ने मतदान केंद्रों की कतारों में खड़े होकर मताधिकार का प्रयोग करके लोकतंत्र के प्रति अपना फर्ज अदा कर दिया। यह दीगर बात है कि अगले पांच वर्षों तक जनप्रतिनिधि सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन पूरी शिद्दत से करेंगे। चुनावों के बाद आम लोगों को अपने सियासी रहनुमां के दीदार दुर्लभ हो जाते हैं। देश का हर चुनाव अपने पीछे कई यादें छोड़ जाता है।

मौजूदा लोकसभा चुनाव में लोगों में मतदान के प्रति उत्साह का माहौल कम था। कई राज्यों में मतदान का प्रतिशत कम रहा, मगर आरोप-प्रत्यारोप के भयानक दौर में शराफत व अदब की हदूद को तोड़ने वाली भाषा के चलते सियासत की दर्जा-ए-हरारत बुलंदी पर पहुंच चुकी थी। गुफ्तगू के दौरान लफ्जों का इस्तेमाल व बात करने का सलीका किसी भी इनसान की तरबियत व परवरिश का बेहतरीन सबूत होता है। जहरीले लफ्जों से उपजे गहरे जख्म दशकों तक नहीं भरते। इंतखाबी तश्हीर के दौरान सियासी रहनुमाओं की जुबान से निकले तीरनुमां लफ्जों ने मुल्क की सियासत को काफी हद तक मफलूज कर दिया है। सियासत के किरदार का अनोखा अंदाज है कि मुल्क में सियासी रहनुमाओं को ही दानिश्वर माना जाता है। देश की अफसरशाही व नौकरशाही तथा तमाम व्यवस्थाएं सियासत के आगे नतमस्तक रहती हैं। आम लोग ज्यादातर समस्याओं के समाधान के लिए जनप्रतिनिधियों से ही अपेक्षा रखते हैं। भोली-भाली विरासत के लोग सियासतदानों के आश्वासनों पर अक्सर विश्वास कर लेते हैं, जबकि सियासत की कथनी और करनी में फर्क होता है। सियासत एक ऐसा पेशा है जिसमें अपने सियासी दुर्ग फतह करने के लिए सियासी रहनुमाओं के झूठ बोलने पर, मौके की नजाकत को भांपकर जाति-मजहब का कार्ड खेलना, वोट बैंक साधने के लिए जराफत भरे अंदाज में लोकलुभावन वादों की बिसात बिछाना तथा चुनावी प्रचार के दौरान की गई घोषणाओं से मुकरने पर कोई कानूनी पाबंदी नहीं है। इसीलिए सियासत के मिजाज से कभी सदाकत की महक नहीं आती। सियासी रहनुमाओं के किरदार में मोहिब्ब-ए-वतन का अक्स नहीं दिखाई देता। इंतखाबी तश्हीर में हिकारत भरे अल्फाज व बड़बोली भाषणबाजी के आगे निर्वाचन आयोग भी बेबस हो चुका है। लेकिन सत्ता की दहलीज पर पहुंचने की होड़ में जनसैलाब को अमर्यादित भाषा से उकसाना तथा लोगों के जज्बात आहत करने की कारकर्दगी मतदाताओं के साथ पूरे जम्हूरी निजाम की तौहीन है। चुनाव आयोग को इस विषय पर संज्ञान लेना होगा। नवगठित मरकजी हुकूमत से देश के करोड़ों लोगों को उम्मीदें रहेंगी, मगर सबसे ज्यादा उम्मीद युवा वर्ग को है। कुछ दर्द इनसान का सुख-चैन छीन कर उसे खामोशी व तन्हाई के आलम में जीने को मजबूर कर देते हैं। बेरोजगारी के सैलाब में फंस चुके युवा वर्ग का हाल कुछ ऐसा ही है। लाइलाज हो चुकी बेरोजगारी के अजाब से युवा वर्ग मानसिक तौर पर मामूर हो चुका है। हर वर्ष हजारों युवा जमीन-जायदाद गिरवी रखकर रोजगार की तलाश में डंकी रूट के जरिए विदेश जाते हैं तथा वहां की सुरक्षा एजेंसियों द्वारा गिरफ्तार किए जाते हैं। विदेशों में पढ़ाई करने वाले भारतीय मूल के छात्रों व रोजगार में लगे युवाओं पर नस्लीय हमले व हत्याएं आम बात हो चुकी है। देश में नशा माफिया के राडार पर भी बेरोजगार युवा हैं। नशाखोरी के मामलों में सलाखों के पीछे भी ज्यादातर युवा वर्ग है। चुनावों में विपक्षी दलों ने बेरोजगारी व महंगाई जैसे ज्वलंत मुद्दों पर जोरदार ताकीद पेश थी। चुनावी संग्राम में नारों व जुमलों का अहम प्रभाव रहता है। लेकिन सियासत चुनावी दौर में मुफ्तखोरी की खैरात व लोकलुभावन वादों से लोगों को लुभाने का प्रयास करती है। खोखले आश्वासनों से लोगों को खुश करने की कोशिश की जाती है, जबकि युवा वर्ग के मन को पढ़ने की जरूरत है। आम लोगों की वास्तविक समस्याओं को महसूस करने की जरूरत है। विश्व में सबसे ज्यादा युवा आबादी की हैसियत रखने वाले भारत में बेरोजगारी की बढ़ती दर तथा मतदान का कम होता प्रतिशत लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए चिंताजनक मसला बन रहा है। मतदान को लेकर लोकतंत्र की बुनियाद मतदाताओं की बेजारी व मतदान के प्रति घटती दिलचस्पी तथा लाखों मतदाताओं द्वारा नोटा के इस्तेमाल पर निष्पक्ष तौर पर रायशुमारी होनी चाहिए। आखिर विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में मतदान का प्रतिशत कम क्यों हो रहा है? चूंकि आधुनिक दौर में लोकतांत्रिक प्रणाली को ही श्रेष्ठ व्यवस्था माना जाता है। लोकतंत्र के पर्व में शिकस्त व जीत का सिलसिला जारी रहेगा, मगर अहम पहलू यह है कि लोकतंत्र में लोगों का भरोसा कायम रहना चाहिए ताकि लोकतांत्रिक व्यवस्था का वजूद महफूज रहे। बहरहाल लोकतंत्र का आधार लोगों के मत पर निर्भर करता है। देश की सियासत को जनता का जनादेश पूरी अकीदत से स्वीकार करना होगा। युवा वर्ग के लिए रोजगार उपलब्ध कराने का मुद्दा सरकारों की प्राथमिकता में होना चाहिए।

सोने के लिए पागल दुनिया: तो क्या ये नए गोल्ड स्टैंडर्ड की आहट है अतीत से सुनें वर्तमान की धड़कन

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) लंदन की तिजोरियों से सोना निकालकर भारत ला रहा है। इन तिजोरियों के इस्तेमाल की अपनी लागत जो है। आरबीआई के पास करीब 822 टन सोने का भंडार है। आरबीआई ने 2019 से 2024 के बीच 209 टन सोना खरीदा है। इतना सोना है, तो इसे संभालने का भी झंझट है। भारत ही क्यों दुनिया भर के केंद्रीय बैंक दबाकर सोना खरीद रहे हैं। चीन ने लगातार 17 महीने सोने की खरीद की। विश्व के केंद्रीय बैंकों के पास अब करीब 2,262 टन सोना जमा है।

सोने की कीमतें अपनी रिकॉर्ड ऊंचाईपर हैं,मगर केंद्रीय बैंक पगलाए हुए सोना जुटाने में लगे हैं। वह भी अब तक की सबसे ऊंची कीमत पर। दुनिया में अब तक जितना सोना निकाला गया है, उसका 20 फीसदी हिस्सा विश्व के केंद्रीय बैंकों की तिजोरियों में है। इस दीवानगी की वजह क्या हैगोल्ड स्टैंडर्ड तो कब का दफनहो गया, जिसमें किसी देश की करेंसी का मूल्यांकन सोने में किया जाता था।केंद्रीय बैंक तो संप्रभु करेंसी के मालिक हैं, जो सोने में नापे जाने की शर्त से मुक्त हैं।बाजार बता रहा है कि बैंकों को दुनिया भर की करेंसी, खासतौर पर डॉलर में गिरावट के डर से उनके विदेशी मुद्रा भंडार सोने की आमद से चमक रहे हैं। घाना 2023 से तेल का भुगतान गोल्ड में कर रहा है।रूस ने युद्ध के दौरान रुबल देकर सोना जुटाने का एलान किया था,तो क्या नए गोल्ड स्टैंडर्ड की आहट है आइए, टाइम मशीन का मोटर गुर्रा रहा है, अपनी सीट पकड़िए और उड़ चलते हैं गोल्ड स्टैंडर्ड की रोमांचक दुनिया में। अब हम अमेरिका के न्यू हैंपशायर के ऊपर से उड़ रहे हैं। पर्वतों से घिरा यह रिजॉर्ट टाउन, जो स्कीइंग के दीवानों का गढ़ है। हम बढ़ रहे हैं 18वीं सदी के आखिरी दशकों की तरफ। यहांकोयला और रेलवे का विकास हो रहा है। कोयला व रेलवे के कारोबार से अमीर बने जोसेफ स्टेकिनी माउंट वॉशिंगटन नाम का होटल बना रहे हैं।

यह होटल 21वीं सदी में मौजूद रहेगा, मगर इससे पहले यह अनोखा इतिहास बनाएगा। टाइम मशीन ने गियर बदला है। अब हम 1944 में हैं।दूसरे विश्वयुद्ध का खून-खच्चरचरम पर है। हम उसी माउंट वॉशिंगटन होटल पर पहुंचे हैं, जो बड़ी जंग के बीच एक बड़े समझौते की तैयारी कर रहा है। यहां 44 देश जुटे हैं, जिनमें ब्रिटिश इंडिया भी है, तालियों की गूंजमें नई आर्थिक व्यवस्था बन गई है। विश्व के प्रमुख देशों ने विश्व बैंक व अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आईएमएफ जैसी संस्थाओं की बुनियाद रख दी है। यहीं से निकल रही है एक नई मौद्रिक व्यवस्था, यानी गोल्ड स्टैंडर्ड। कागजी मुद्रा का सोने में मूल्यांकन। एक औंस सोने के बदले 35 अमेरिकी डॉलर, दुनिया ने मिलकर अमेरिका को गोल्ड स्टैंडर्ड का संचालक बना दिया है। अमेरिका को इस पैमाने को कायम रखना है। मतलब, अगर सोने की विनिमय दर 35 डॉलर से नीचे जाती, तो अमेरिका को डॉलर छापकर इसे संतुलित करना होता था। गोल्ड स्टैंडर्ड के साथ ही उस वक्त की तीन बड़ी मुद्राओं-ब्रिटिश पाउंड, जर्मन मार्क, फ्रेंच फ्रैंक के विनिमय का आधार अमेरिकी डॉलर हो गया है। मौद्रिक स्टैंडर्ड का यह अनोखा प्रयोग है, जिसे युद्ध से उबरती दुनिया ने अपना लिया है। अब बढ़ते हैं 1960 के फ्रांस की तरफ, जहां दिखेगी एक अनोखी कूटनीतिक जंग। बताते चलें कि 1960 के बाद वक्त ने करवट ली। जापान और यूरोप का निर्यात तेजी से बढ़ा। विश्व व्यापार में अमेरिका का हिस्सा घटने लगा।अमेरिकी डॉलर की मांग कम हो गई, तो दुनिया के देश अमेरिका से डॉलर के बदले सोना मांगने लगे।इसी दौरान अमेरिका में रक्षा खर्च बढ़ाने के लिए और ज्यादा करेंसी छापी गई। आपके सामने अखबारों की सुर्खियांतैर रही हैं,जो बता रही हैं कि बाजार में अमेरिका के डॉलर ज्यादा हो गए व अमेरिका के पास सोना कम रह गया। इसके साथ ही दुनिया के मुद्रा बाजार में अमेरिका की ताकत कम होने लगी।

अब हम पेरिस में हैं। माइक पर गरज रहे फ्रांस के राष्ट्रपति चार्ल्स डे गॉल ने फ्रांस के नए राजनीतिक दौरकी शुरुआत की है।पेरिस की राजनीतिक हवा में आपको यह पता चल जाएगा कि यूरोप के सबसे तेज-तर्रार नेताओं में से एक चार्ल्स डे गॉल अमेरिका विरोधी हैं। फ्रेडी रूजवेल्ट से लेकर रिचर्ड निक्सन तक छह अमेरिकी राष्ट्रपतियों के साथ उनके रिश्तेज्यादातर खट्टे रहे हैं।अब चार्ल्स डे गॉल ने अमेरिकी अगुआई वाले गोल्ड स्टैंडर्ड को निशाना बनाया है। गॉल ने फ्रांस में अमेरिका से डॉलर के बदले सोना लेना शुरू कर दिया है।इस कदम का रहस्य खुलने तक फ्रांस करीब 15.करोड़ डॉलर के बदले सोना दे चुका है।

अब खबरों पर नजर जमाइए।डे गॉल ने एलान कर दिया है कि फ्रांस के पास जितने भी अमेरिकी डॉलर हैं, उनके बदले वह अमेरिका से सोना वसूल करेगा। किसी मित्र देश की तरफ से यह अमेरिका पर सबसे बड़ा कूटनीतिक हमला है। फ्रांस के बाद स्पेन ने भी अमेरिका से सोना वसूल लिया। अब बाजार में सोने की कीमत खौलने लगी है। यह अक्तूबर,1960 है, जब सोने की कीमत रिकॉर्ड 40 डॉलर प्रति औंस तक पहुंच गई। अब हम लंदन चलते हैं, ब्रिटेन, पश्चिम जर्मनी, इटली, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, नीदरलैंड व अमेरिका ने मिलकर लंदन गोल्ड पूल बनाया है।इन देशों के पास उपलब्ध सोने के भंडारों के इस्तेमाल से गोल्ड स्टैंडर्ड को बचाने की कोशिश की गई है।इस भंडार के जरिये 35 डॉलर प्रति औंसकी कीमत को बचाया जा रहा है। इस गठजोड़ में दरारों पर नजर रखते हुए हमारी टाइम मशीन 1968 में आ गई है। फ्रांस ने इससे नाता तोड़ लिया है और लंदन गोल्ड पूल ढह गया।दुनिया में गोल्ड स्टैंडर्ड की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। सोने की खबरों के बीच आपको पता चलेगा कि 1962 में अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने दुनिया के नौ केंद्रीय बैंकों के साथ एक स्वैप सुविधा शुरू की थी। इनमें ब्रिटेन, तब का पश्चिम जर्मनी, इटली, फ्रांस और कनाडा प्रमुख थे। कोशिश थी कि डॉलर के बदले सोने की मांग सीमित व संतुलित की जा सके, लेकिनअमेरिका के मौद्रिक सिस्टम की दरारें खुल चुकी थीं। सोना कम था व डॉलर की भरमार थी। अंततः गोल्ड स्टैंडर्ड का अंत आ पहुंचा। टाइम मशीन लंदन से वॉशिंगटन आ गई है। यह 1971 का ऐतिहासिकवर्ष है। अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन ने डॉलर की सोने से परिवर्तनीयता खत्म कर दी। अमेरिका में गोल्ड के आयात पर दस फीसदी इंपोर्ट ड्यूटी लगा दी गई।गोल्ड स्टैंडर्ड खत्म हो गया। सोना दुनिया की आधारभूत मुद्रानहीं रहा है। नई मौद्रिक प्रणाली में डॉलर नई आधारभूत मुद्रा थी। अब संप्रभु करेंसी सोने पर आधारित नहीं थी। इसलिए इनमें तेज उतार-चढ़ाव होने लगा। इसका बड़ा लाभ यह है कि अर्थव्यवस्था की जरूरत के लिए मुद्रा छापी जा सकती थी, मगर छापाखानों से आगे महंगाई भी निकलने लगी थी। नजर आएगा कि नई मौद्रिक प्रणाली का उद्घाटन अमेरिका में ग्रेट इन्फ्लेशन यानी महा महंगाई के साथ हो रहा है। टाइम मशीन वापस 2024 में आ गई है। हम अब मुंबई में हैं, जहां रिजर्व बैंक लंदन से सोना लाने की तैयारी में लगा है। दुनिया के बैंक डॉलर बेचकर सोना जुटा रहे हैं।उनके विदेशी मुद्रा भंडार में सोने का हिस्सा बढ़ रहा है। संप्रभु मुद्राएं टूट रही हैं। महंगाई जिद्दी हो चली है।सोने की कीमत रिकॉर्ड बना रही है। लोग पूछ रहे हैं, कि जब सोना सस्ता होगा, तब ये बैंक क्या करेंगेइनके विदेशी मुद्रा भंडारों की कीमत टूटेगी, तो मुद्राओं का क्या होगा या फिर सारे बैंक मिलकर सोने की महंगाई को स्थायी बना देंगे बड़ा ही दिलचस्प मौद्रिक दौरहै यह।

मृणाल जल्द करने वाली हैं तमिल डेब्यू, इस हॉरर कॉमेडी फ्रेंचाइजी का बन सकती हैं हिस्सा

मृणाल ठाकुर इन दिनों व्यस्तम अभिनेत्रियों में से एक हैं। उन्होंने सीता रामम और हाय नन्ना जैसी फिल्मों में शानदार अभिनय कर दर्शकों का दिल जीत लिया। हाल में ही वह फिल्म द फैमिली स्टार में अभिनेता विजय देवरकोंडा के साथ नजर आई थीं। अभिनेत्री ने अपने अब तक के करियर में अपनी बहुमुखी अदाकारी का परिचय दिया है। वह हिंदी के अलावा दक्षिण भारतीय फिल्मों में भी अपना जलवा बिखेर रही हैं। मलयालम,तेलुगु के बाद अब वह तमिल फिल्मों में भी डेब्यू करने जा रही हैं।

कंचना 4 से जुड़ सकती हैं मृणाल ठाकुर

एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, हॉरर कॉमेडी फ्रेंचाइजी कंचना के चौथे भाग के लिए मृणाल से संपर्क किया गया है। अभिनेता सह निर्देशक राघव लॉरेंस कंचना 4 की अगली कड़ी पर काम करना चाहते हैं। इस हॉरर-कॉमेडी फिल्म से वह न केवल बतौर मुख्य अभिनेता, बल्कि बतौर निर्देशक भी जुड़ने वाले हैं। अगर फिल्म में मृणाल ठाकुर के काम करने की खबरें सच साबित होती हैं, तो उनके फैंस के लिए उन्हें तमिल फिल्मों में देखना काफी दिलचस्प रहेगा। हालांकि, अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि होनी अभी बाकि है।

हॉरर के साथ मिलता है कॉमेडी का तड़का

राघव लॉरेंस की कंचना फ्रेंचाइजी पिछले कुछ सालों में व्यावसायिक रूप से काफी सफल रही है। इसकी हर फिल्म में हॉरर के साथ कॉमेडी का तड़का देखने को मिला है। कंचना तमिल भाषा की बेहद सफल हॉरर कॉमेडी फ्रेंचाइजी है। कंचना को मुनि के नाम से भी जाना जाता है। मुनि साल 2007 में रिलीज हुई थी। फिल्म में राघव लॉरेंस, सरथकुमार, लक्ष्मी राय आदि कलाकार नजर आए थे।

कंचना 3 ने की थी 100 करोड़ से भी यादा की कमाई

मुनि के बाद इस का अगला भाग मुनि 2 साल 2011 में रिलीज हुआ था। इसे कंचना 2 के नाम से भी जाना जाता है, जिसके बाद इस फ्रेंचाइजी की तीसरी कड़ी कंचना 3 साल 2019 में रिलीज हुई थी, जिसने 100 करोड़ से भी यादा की कमाई की थी। अब निर्माता इसके चौथे भाग पर काम शुरू कर रहे हैं, जिससे अभिनेत्री मृणाल ठाकुर के जुड़ने की खबरें आ रही हैं।

शनिवार को कैसा रहा बॉक्स ऑफिस का हाल जानें मुंजा से लेकर श्रीकांत तक की कमाई

सिनेमाघरों में इन दिनों कई फिल्में प्रदर्शित हो रही हैं, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर कोई भी फिल्म लंबे समय से बंपर ओपनिंग नहीं ले सकी है। हाल ही में रिलीज हुई मुंजा और बैड बॉयज राइड ऑर डाई उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर सकी हैं। वहीं, इन दोनों के अलावा अन्य फिल्में बॉक्स ऑफिस पर टिके रहने के लिए लगातार संघर्ष कर रही हैं। आइए जानते हैं कि शनिवार को कौन सी फिल्म ने कितनी कमाई की। अभिनेता अभय वर्मा और शरवरी वाघ की हॉरर कॉमेडी फिल्म मुंजा 7 जून को रिलीज हुई थी। पहले दिन फिल्म ने 4 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था। वहीं, दूसरे दिन फिल्म की कमाई में उछाल नजर आया। शनिवार को इस फिल्म ने छह करोड़ 75 लाख रुपये का कलेक्शन किया। इसके साथ ही फिल्म की कुल कमाई 10.82 करोड़ रुपये हो गई है। बैड बॉयज राइड ऑर डाई में विल स्मिथ और मार्टिन लॉरेन्स ने मुख्य भूमिकाएं निभाई हैं। हालांकि, भारत में फिल्म को उम्मीद के मुताबिक ओपनिंग नहीं मिल सकी है। दो दिन में फिल्म ने 76 लाख रुपये का बिजनेस किया था। वहीं, तीसरे दिन 86 लाख रुपये का कलेक्शन किया। फिल्म की कुल कमाई अब एक करोड़ 62 लाख रुपये हो गई है। मिस्टर एंड मिसेज माही भी टिकट खिड़की पर धीमी रफ्तार से आगे बढ़ रही है। फिल्म में राजकुमार राव और जान्हवी कपूर के किरदार को भले ही पसंद किया जा रहा हो, लेकिन यह फिल्म सिनेमाघरों में भीड़ बटोरने में कामयाब नहीं हो सकी है। पहले हफ्ते में इस फिल्म ने 24.45 लाख रुपये का कलेक्शन किया था। शुक्रवार को फिल्म ने एक करोड़ 30 लाख रुपये का कलेक्शन किया था। वहीं, शनिवार को फिल्म की कमाई थोड़ा सुधार नजर आया। नौवें दिन फिल्म ने दो करोड़ 15 लाख रुपये के साथ 27.91 करोड़ रुपये का कुल कलेक्शन कर लिया। राजकुमार राव की फिल्म श्रीकांत भी सिनेमाघरों में चल रही है। हालांकि, फिल्म की रफ्तार काफी ज्यादा सुस्त है। चौथे हफ्ते में इस फिल्म ने पांच करोड़ 35 लाख रुपये का बिजनेस किया था। 30वें दिन फिल्म ने 52 लाख रुपये की कमाई की है। इसके साथ ही फिल्म की कुल कमाई 46.46 करोड़ रुपये हो गई है।

कल्कि 2898 एडी के ट्रेलर लॉन्च को भव्य बनाने की तैयारी, जानें क्या खास करने जा रहे हैं निर्माता

कल्कि 2898 एडी इस साल की बहुप्रतीक्षित फिल्मों में से एक हैं। इसका इंतजार न सिर्फ दक्षिण भारत के लोगों को है, बल्कि इस फिल्म को देखने के लिए हिंदी पट्टी के लोग भी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। महानति जैसी सुपरहिट फिल्म बना चुके नाग अश्विन ने इस फिल्म का निर्देशन किया है। यह पहला मौका है जब प्रभास और नाग अश्विन एक साथ किसी फिल्म में काम कर रहे हैं। कल्कि 2898 एडी का ट्रेलर 10 जून को रिलीज करने की तैयारी है। फिल्म के निर्माता इस ट्रेलर लॉन्च कार्यक्रम को भव्य तरीके से आयोजित करने की जोर शोर से तैयारी कर रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार निर्माताओं ने लोगों में फिल्म को लेकर उत्साह बरकरार रखने के लिए खास योजना बनाई है। रिपोर्ट्स की मानें तो इस फिल्म के ट्रेलर को दक्षिण के कई सिनेमाघरों में दिखाया जाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार फिल्म के ट्रेलर को मुंबई के भी कई सिनेमाघरों में फैंस के लिए प्रदर्शित किया जाएगा। इसके अलावा देश के अन्य हिस्सों में भी ट्रेलर को बड़े पर्दे पर दिखाने की योजना पर फिल्म के निर्माता काम कर रहे हैं। फिल्म की स्टारकास्ट की बात करें तो इसमें अमिताभ बच्चन, दीपिका पादुकोण और कमल हासन जैसे बड़े सितारे भी मौजूद हैं। हाल ही में अमिताभ बच्चन का एक पोस्टर जारी किया गया था, जिसे देखने के बाद फैंस में और अधिक उत्सुकता बढ़ गई है।कल्कि 2898 एडी 27 जून को सिनेमाघरों में प्रदर्शित होनी है। उम्मीद जताई जा रही है कि बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म धमाकेदार शुरुआत करेगी। वर्क फ्रंट की बात करें तो इस फिल्म के बाद प्रभास राजा साब नाम की फिल्म में नजर आएंगे। फिल्म का निर्देशन मारुति दसारी कर रहे हैं।

जिस निर्देशक के साथ किया था डेब्यू, उसी की हिट फिल्म में काम करने से चूक गए थे विजय

अभिनेता विजय देवरकोंडा को लंबे समय से हिट फिल्म का इंतजार हैं। उनकी पिछली फिल्म द फैमिली स्टार ने बॉक्स ऑफिस पर खराब प्रदर्शन किया था। फिल्म दर्शकों के लिए तरस गई थी। विजय और उनके फैंस को उनकी आने वाली एक्शन ड्रामा फिल्म से काफी उम्मीद है। यह फिल्म ग्रामीण पृष्ठभूमि पर आधारित होगी, जिसमें विजय के किरदार को देखना काफी दिलचस्प होगा। इस फिल्म का निर्देशन रवि किरण कोला कर रहे हैं। हाल ही में, विजय के करियर से जुड़ी एक बड़ी जानकारी सामने आई है।

अवुनु फिल्म में कास्ट होने से रह गए थे विजय

विजय देवरकोंडा ने साल 2011 में नुव्विला फिल्म से अभिनय की दुनिया में कदम रखा था। इस फिल्म का निर्देशन करने वाले रवि बाबू ने एक साक्षात्कार में खुलासा करते हुए बताया कि विजय देवरकोंडा उनकी फिल्म अवुनु का हिस्सा हो सकते थे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। इसकी वजह बताते हुए रवि बाबू ने कहा कि विजय को पूर्णा के पति का किरदार निभाना था, मगर कुछ संवादों के चलते समस्या खड़ी हो गई थी और वो विजय को फिल्म में नहीं ले पाए थे। मालूम हो कि यह एक हॉरर थ्रिलर फिल्म है, जिसे दर्शकों की ओर से अछी प्रतिक्रिया मिली थी। इस फिल्म में हर्षवर्धन राणे, सुधा और जीवा ने भी अभिनय किया था।

वीडी 12 पर भी चल रहा है काम

विजय देवरकोंडा निर्देशक गौतम तिन्नानुरी के साथ भी एक फिल्म पर काम कर रहे हैं। यह एक थ्रिलर फिल्म होगी। फिलहाल इसे वीडी 12 नाम दिया गया है। इस फिल्म का निर्माण सीथारा एंटरटेनमेंट्स और फॉर्च्यूर फोर सिनेमाज द्वारा किया जाएगा। कहा जा रहा है कि अभिनेत्री भाग्यश्री बोरसे भी फिल्म का हिस्सा हो सकती हैं। इसका संगीत अनिरुद्ध रविचंदर तैयार कर रहे हैं।

बॉक्स ऑफिस पर फिर से दिखेगा चांदनी चौधरी का जलवा, एक ही दिन में रिलीज होगी दो फिल्में

दक्षिण भारतीय अभिनेत्री चांदनी चौधरी के लगातार हिट फिल्में दे रही हैं। यही वजह है कि दर्शक उनकी आने वाली फिल्मों पर नजर बनाए हुए हैं, लेकिन इस बार दर्शक भी सोच में पड़ गए है। दरअसल, आने वाली 14 जून को चांदनी की दो फिल्में रिलीज होने वाली है और उनके फैंस के लिए तय करना मुश्किल है कि कौन सी फिल्म पहले देखें और कौन सी बाद में।

एक दिन रिलीज होगी येवम और म्यूजिक शॉप मूर्ति

14 जून, 2024 को चांदनी की, जो दो फिल्में रिलीज होने वाली हैं, उनमें से एक है- येवम और दूसरी है- म्यूजिक शॉप मूर्ति। येवम एक मनोवैज्ञानिक थ्रिलर है। इस फिल्म में चांदनी पुलिस अधिकारी का रोल निभा रही हैं, जिसे देखना काफी दिलचस्प होगा। चांदनी की इन दोनों ही फिल्मों के ट्रेलर को लोगों ने काफी पसंद किया है, इससे उम्मीद है कि एक बार फिर से बॉक्स ऑफिस पर चांदनी की फिल्मों का जलवा देखने को मिलेगा।

प्रकाश दंतुलुरी ने किया येवम का निर्देशन

येवम का निर्देशन प्रकाश दंतुलुरी ने किया है। इस फिल्म में चांदनी चौधरी के अलावा भरत राज, आशु रेड्डी और वसिष्ठ सिम्हा ने भी काम किया है। फिल्म का निर्माण नवदीप और पवन गोपाराजू ने किया है। कीर्तना सेश और नीलेश मंडलपु ने फिल्म को अपनी धुनों से सजाया हैं।

म्यूजिक शॉप मूर्ति में कलाकार आएंगे नजर

म्यूजिक शॉप मूर्ति का निर्देशन शिव पलाडुगु ने किया है। उन्होंने ही इस फिल्म की कहानी भी लिखी है। इस फिल्म में चांदनी के साथ-साथ अजय घोष भी मुख्य भूमिका निभा रहे हैं। इन दोनों के अलावा अमित शर्मा, भानु चंद्र, अमानी और दयानंद रेड्डी भी अभिनय करते नजर आएंगे। इस फिल्म का निर्माण फ्लाई हाई सिनेमा के बैनर तले हर्ष गरपति और रंगा राव गरपति ने किया है। बता दें कि चांदनी की पिछली फिल्में सबा नायगन और गामी बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई थी।

सोनम कपूर ने 11 रुपये में किया था एक फिल्म में काम, भाग मिल्खा भाग से चमका था करियर

सांवरिया फिल्म से अपने अभिनय करियर की शुरूआत करने वाली अभिनेत्री सोनम कपूर आज अपना 39वां जन्मदिन मना रही हैं। उनका जन्म 9 जून, 1985 को मुंबई में हुआ था। सोनम लंबे समय से फिल्मों से दूर हैं, लेकिन अपने बेबाक अंदाज और फैशन के कारण आए दिन चर्चा में बनी रहती हैं। उनका अभी तक का करियर उतार-चढ़ाव वाला रहा है।सोनम की शुरूआती पढ़ाई-लिखाई जुहू स्थित आर्य विद्या मंदिर स्कूल में हुई थी। इसके बाद उन्होंने सिंगापुर के यूनाइटिड वर्ल्ड कॉलेज ऑफ साउथ ईस्ट एशिया से थिएटर और आर्ट्स की पढ़ाई की। उन्होंने सिंगापुर में कुछ दिन के लिए वेटर का काम भी किया था। भारत लौटने पर उन्होंने संजय लीला भंसाली की फिल्म ब्लैक में सहायक निर्देशक के तौर पर काम किया था। बाद में साल 2007 में भंसाली की ही फिल्म सांवरिया से उन्होंने एक्टिंग की दुनिया में कदम रखा था, जो बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह से फ्लॉप हुई थी। हालांकि, सोनम कपूर को बेस्ट फीमेल डेब्यू के फिल्मफेयर अवॉर्ड के लिए नॉमिनेट किया गया था।सांवरिया के बाद सोनम कपूर ने साल 2009 में राकेश ओमप्रकाश मेहरा की फिल्म दिल्ली 6 में काम किया था। फिल्म को मिली जुली प्रतिक्रियाएं मिली थी। इसके अगले साल सोनम आई हेट लव स्टोरीज में नजर आई थीं, जो बॉक्स ऑफिस पर अछा कारोबार करने में कामयाब हुई थी। इसके बाद उन्होंने अभय देओल के साथ आयशा की थी। सोनम को अक्षय कुमार, बॉबी देओल और इरफान खान के साथ थैंक्यू और शाहिद कपूर के साथ मौसम फिल्म में अपने अभिनय के लिए आलोचना का सामना करना पड़ा था। 2012 में आई प्लेयर्स फिल्म पर भी फ्लॉप का ठप्पा लगा था।लगातार फ्लॉप पर फ्लॉप फिल्में देने के बाद सोनम कपूर ने आखिरकार साल 2013 में जाकर रांझना फिल्म से तारीफें बटोरीं। इस फिल्म के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के फिल्मफेयर पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। यहां से उनका करियर संवरने लगा था। उसी साल भाग मिल्खा भाग ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाया। इस फिल्म के जरिए सोनम कपूर ने दूसरी बार राकेश ओमप्रकाश मेहरा के साथ काम किया था। खास बात यह है कि इस फिल्म के लिए सोनम ने फीस के तौर पर केवल 11 रुपये लिए थे। इन दो सफलताओं के बाद एक बार फिर से सोनम के करियर का पहिया पटरी से उतर गया। 2014 में आई बेवकूफियां और खूबसूरत फिल्म बॉक्स ऑफिस पर आने के साथ ही सुस्त पड़ गई थी।सोनम कपूर और सलमान खान की फिल्म प्रेम रतन धन पायो ने बॉक्स ऑफिस पर तगड़ी कमाई की थी। नीरजा के लिए सोनम ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्मफेयर क्रिटिक अवॉर्ड जीता था। साल 2018 में उन्होंने पैडमैन फिल्म से एक बार फिर अक्षय कुमार के साथ काम किया था। उसी साल उन्होंने उद्योगपति आनंद आहूजा से शादी कर ली थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, अब तक सोनम कपूर की 11 फिल्में फ्लॉप हो चुकी हैं। शादी के बाद वो वीरे दी वेडिंग, संजू, एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा, द जोया फैक्टर और एके वर्सेज एके फिल्म में नजर आई थीं। उनकी पिछली फिल्म ब्लाइंड थी, जो साल 2023 में रिलीज हुई थी।

कंगना रणौत के थप्पड़ कांड से नाखुश ऋतिक रोशन, विवाद के आठ साल बाद जताई हमदर्दी

अभिनेत्री से नेता बनीं कंगना रणौत को गुरुवार दोपहर चंडीगढ़ हवाईअड्डे पर सीआईएसएफ कर्मी ने थप्पड़ मार दिया। हिमाचल प्रदेश के मंडी निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा चुनाव जीतने के कुछ दिनों बाद कंगना नई दिल्ली की यात्रा कर रही थीं। कुलविंदर कौर नाम की सीआईएसएफ महिला कांस्टेबल को निलंबित कर दिया गया है। सीआईएसएफ अधिकारियों की लिखित शिकायत के आधार पर चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर सीआईएसएफ कांस्टेबल के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जा रही है। सीआईएसएफ की ओर से स्थानीय पुलिस में भी शिकायत दर्ज कराई गई है। वहीं, अब इस विवाद पर कंगना के एक्स बॉयफ्रेंड ऋतिक रोशन की भी प्रतिक्रिया सामने आई है, जो लोगों का खासा ध्यान आकर्षित कर रहा है।

पत्रकार ने लिया कंगना का पक्ष

स्वतंत्र पत्रकार फेय डिसूजा ने इस कृत्य की निंदा करते हुए एक पोस्ट डाला। उन्होंने लिखा, सांसद कंगना रणौत को हवाईअड्डे पर थप्पड़ मारे जाने की घटना के संदर्भ में, हिंसा कभी भी जवाब नहीं हो सकती। खासकर हमारे देश में तो बिल्कुल नहीं, जो गांधीजी के अहिंसा के आदर्शों से पैदा हुआ था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम किसी के विचारों और बयानों से कितना असहमत हैं, हम हिंसा से प्रतिक्रिया नहीं कर सकते और हमें इसकी निंदा नहीं करनी चाहिए। यह विशेष रूप से खतरनाक होता है जब सुरक्षाकर्मी वर्दी में रहते हुए हिंसक प्रतिक्रिया करते हैं। कल्पना कीजिए, पिछले दस वर्षों में, अगर हममें से जो लोग सत्ता पर सवाल उठाते थे, उन पर हवाईअड्डों पर उन कांस्टेबलों द्वारा हमला किया गया जो उस सत्ता से सहमत थे।

सितारों ने पोस्ट लाइक कर दिया समर्थन

फेय डिसूजा की इस पोस्ट पर ऋतिक रोशन ने लाइक किया है, जिसे देखकर लोग यह मान रहे हैं कि अभिनेता भी इस थप्पड़ की घटना से खुश नहीं हैं। ऋतिक के अलावा सोनाक्षी सिन्हा, एकता कपूर, आलिया भट्ट, भूमि पेडनेकर, अर्जुन कपूर और राजकुमार राव ने भी पत्रकार की पोस्ट को लाइक कर अपना समर्थन दिया है।

कंगना-ऋतिक का विवाद

कथित तौर पर कंगना रणौत और ऋतिक रोशन का अफेयर फिल्म कृष 3 की शूटिंग के दौरान शुरू हुआ था, लेकिन कुछ समय बाद ही दोनों ने अपनी राहें अलग कर लीं। इसके बाद कंगना ने एक इंटरव्यू में ऋतिक को खुले तौर पर अपना एक्स बताया। साथ ही अभिनेता को लेकर कई चौंकाने वाले दावे भी किए थे। 2016 में शुरू हुआ दोनों का विवाद अब तक बरकरार है। हालांकि, इस बीच पत्रकार की पोस्ट को लाइक कर ऋतिक थप्पड़ की घटना से असहमति जाहिर करते नजर आए हैं।

चरस कारोबारी को अदालत ने सुनाई तीन वर्ष के कारावास की सजा

30 हजार रूपए का अर्थदंड भी लगाया

गौरव सिंघल । सिटी चीफ ।
सहारनपुर। वर्ष 2019 में चरस तस्करी के मामले में अदालत ने मुर्तबा आलम को तीन साल के कारावास की सजा सुनाई है तथा 30 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। बता दें, कि सन 2019 में थाना फतेहपुर के वरिष्ठ उपनिरीक्षक अजय प्रसाद गौड़ द्वारा चेकिंग के दौरान चरस तस्कर मुर्तबा आलम पुत्र अकरम निवासी ग्राम भटपुरा थाना फतेहपुर को 228 ग्राम अवैध चरस के साथ गिरफ्तार किया था। वरिष्ठ उपनिरीक्षक अजय प्रसाद गौड़ ने अभियुक्त मुर्तबा आलम के विरुद्ध दिनांक 28-3-2019 में थाना फतेहपुर में आईपीसी की धारा 8/20 एनडीपीएस में एक मुकदमा पंजीकृत करते हुए गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। लगभग 5 साल लगातार चले इस मामले में माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-11 द्वारा द्वारा अभियुक्त मुर्तबा आलम को तीन साल कारावास

की सजा सुनाई गई तथा 30 हजार रूपए का अर्थदंड भी लगाया गया।

सहारनपुर के देवबंद में घर में हुई चोरी, सहन में सो रहे थे घर वाले

छत के रास्ते घर में घुसे चोर, अलमारी का ताला तोड़कर सोने-चांदी के जेवर और नकदी चोरी कर ले गए

गौरव सिंघल । सिटी चीफ ।
सहारनपुर । देवबंद, देवबंद कोतवाली क्षेत्र के गांव अंबेहटा शेखां में छत के रास्ते घर में घुसे चोर अलमारी का ताला तोड़कर सोने-चांदी के जेवर और नकदी चोरी कर ले गए। चोर इतने शातिर थे कि सहन में सो रहे घर वालों को उनकी आहट तक नहीं हुई। सुबह होने पर ही घटना का पता चला। पीड़ित ग्रामीण ने पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। प्राप्त जानकारी के अनुसार देवबंद कोतवाली क्षेत्र के गांव अंबेहटा शेखां निवासी रिजवान और उसका परिवार बीती रात अपने घर के सहन में सो रहा था। रात के समय चोर छत के रास्ते उसके घर में घुस गए और कमरे में रखी अलमारी का ताला तोड़ते हुए अंदर रखी 35 हजार रुपये की

नकदी और सोने- चांदी के जेवर चोरी कर ले गए। कमरे में रखे दो मोबाइल भी चोर अपने साथ ले गए। सुबह जब रिजवान और उसका परिवार जागा तो कमरे का नजारा देख उनके होश उड गए। उन्होंने तुरंत घटना की सूचना पुलिस को दी गई। जिसके बाद पुलिस गांव में पहुंची और जांच-पडताल की। पीड़ित रिजवान ने बताया कि शायद कूलर चलने की आवाज के कारण उन लोगो को चोरो के आने का आभास नहीं हो पाया। रिजवान ने बताया कि चोर उसका दो लाख रुपये से अधिक का सामान, जेवर व नकदी चोरी कर ले गए है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है।

मेपल्स एकेडमी के विद्यार्थियों ने नीट परीक्षा में उत्कृष्ठ प्रदर्शन कर विद्यालय व अपने माता-पिता का नाम किया रोशन

विद्यार्थियों ने अपनी सफलता का श्रेय अपने माता-पिता एवं स्कूल को दिया

गौरव सिंघला सिटी चीफ ।
सहारनपुर । देवबंद, मेपल्स एकेडमी के विद्यार्थियों ने नीट परीक्षा-2024 में उत्कृष्ठ प्रदर्शन कर विद्यालय व अपने माता-पिता का नाम रोशन किया है। नीट परीक्षा में शुभी मित्तल ने कुल 720 में से 682 अंक, प्रशान्त पुंडीर ने 620 अंक तथा हर्ष गोयल ने 606 अंक प्राप्त किए। विद्यार्थियों ने अपनी सफलता का श्रेय अपने माता-पिता एवं स्कूल को दिया। विद्यालय की प्रधानाचार्या एवं समस्त अध्यापकों ने विद्यार्थियों के उज्ज्वल भविष्य की कामना की और उसके परिवार को बधाई दी। विद्यालय की प्रधानाचार्या डॉ. चित्रा जोशी ने छात्राओं की सफलता पर प्रसन्नता जताते हुए उन्हें भविष्य में और बेहतर करने का आशीर्वाद देकर शुभकामनाएँ देते हुए कहा कि बच्चों की ऐसी सफलता से स्कूल के अन्य विद्यार्थियों को भी प्रेरणा मिलती है।

पुलिस अधीक्षक यातायात सिद्धार्थ वर्मा बने सीनियर एडिशनल एसपी

एसएसपी ने उनके कंधे पर सीनियर स्केल की प्रोन्नति का स्टार लगाया तथा उनके उज्ज्वल भविष्य की

गौरव सिंघल । सिटी चीफ ।
सहारनपुर, पुलिस अधीक्षक यातायात सिद्धार्थ वर्मा की सीनियर एडिशनल एसपी के पद पर पदोन्नति हुई है। एसएसपी सहारनपुर डॉ विपिन ताड़ा ने विधिवत रूप से सिद्धार्थ वर्मा के कंधे पर सीनियर स्केल की प्रोन्नति का स्टार लगाया तथा उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। बता दे कि सिद्धार्थ वर्मा की चुनाव में नोडल अधिकारी के रूप में अपनी जिम्मेदारियों के निर्वहन करने को लेकर भी सराहना हो रही है। यही नहीं सहारनपुर में यातायात की उत्तम व्यवस्था को लेकर सभी उनकी प्रशंसा की जाती है। एसपी ट्रैफिक के पद को संभालते के बाद सिद्धार्थ वर्मा द्वारा ट्रैफिक नियमों के बारे में घूम-घूम कर लोगों को जागरूक किया गया और सड़क निर्माण के दौरान भी यातायात की बेहतर व्यवस्था देने के लिए आम जनमानस एसपी ट्रैफिक सिद्धार्थ वर्मा की प्रशंसा करता रहा है।

सहारनपुर में दर्दनाक हादसे में एक युवक की हुई मौत

साथी हुआ गंभीर रूप से घायल

गौरव सिंघल । सिटी चीफ ।
सहारनपुर, सहारनपुर जनपद के गागलहेड़ी में भगवानपुर रोड पर ट्रक को ओवरटेक कर रहे बाइक सवार सामने आ रहे ट्रैक्टर-ट्रॉली से टकरा गए। हादसे में एक युवक की मौत हो गई, जबकि दूसरा घायल हो गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार सहारनपुर जनपद के शारदा नगर निवासी रोहित चौधरी (25) पुत्र अमरजीत सिंह व उसका साथी चरणजीत सिंह पुत्र मोनू बाइक पर सवार होकर देर रात हरिद्वार जा रहे थे। भगवानपुर रोड पर हरियाबॉस के निकट पहुंचते ही ट्रक को ओवरटेक करने के प्रयास में उनकी टक्कर सामने

आ रही ट्रैक्टर-ट्रॉली से हो गई। हादसे में रोहित की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसका साथी चरणजीत सिंह गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। घायल को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने ट्रैक्टर-ट्रॉली को कब्जे में लेकर चालक को हिरासत में ले लिया है।

देवबंद के दून वैली पब्लिक स्कूल के छात्र राघव सिंघल ने CAT परीक्षा में प्रथम प्रयास में ही सफलता प्राप्त कर स्कूल और क्षेत्र का नाम किया रोशन

छात्र राघव सिंघल ने अपनी सफलता का श्रेय अपने शिक्षकों और परिवार को दिया और कहा कि वह भविष्य में भी इसी प्रकार मेहनत करके और भी ऊंचाइयों को छूना चाहता है

गौरव सिंघल । सिटी चीफ
सहारनपुर । देवबंद, दून वैली पब्लिक स्कूल देवबंद के छात्र राघव सिंघल ने कॉमन एडमिशन टेस्ट) में सफलता प्राप्त कर अपने स्कूल और देवबंद नगर का नाम रोशन किया है। छात्र राघव सिंघल ने अपनी मेहनत और लगन से इस प्रतिष्ठित परीक्षा में प्रथम प्रयास में 99.6 परसेंटाइल प्राप्त कर उच्च रैंक हासिल की है तथा देश के अति प्रतिष्ठित कॉलेज आई? आई? एम? (इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट) इंदौर में प्रवेश प्राप्त किया है। इस अवसर पर स्कूल के चेयरमैन राजकिशोर गुप्ता ने छात्र को बधाई दी और उसकी मेहनत की सराहना की। उन्होंने कहा कि इस सफलता के पीछे छात्र राघव सिंघल का कठिन परिश्रम, विद्यालय के शिक्षकों का मार्गदर्शन और माता-पिता का सहयोग रहा है। इस उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए विद्यालय अत्यंत गौरवान्वित है। विद्यालय प्रशासन ने अपनी प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि यह उपलब्धि उनके लिए गर्व का विषय है और यह दर्शाता है कि उन्होंने जिस उद्देश्य को लेकर द दून वैली

RAAGHAV 4816
DOON VALLEY ,DEOBAND

की नींव रखी गयी थी उसको पूर्ण करने में विद्यालय का प्रत्येक छात्र, माता-पिता व शिक्षक पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध है । छात्र राघव सिंघल ने अपनी सफलता का श्रेय अपने शिक्षकों और परिवार को दिया और कहा कि वह भविष्य में भी इसी प्रकार मेहनत करके और भी ऊंचाइयों को छूना चाहता है।
यह सफलता देवबंद नगर के लिए गर्व का विषय है और अन्य छात्रों को भी प्रेरित करेगी कि वे भी कठिन परिश्रम और समर्पण से किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। छात्र के माता-पिता तथा क्षेत्रवासी भी अत्यंत उत्साहित हैं। सभी लोगो ने राघव सिंघल के स्वर्णिम भविष्य की आकांक्षा की है।

मिथ्याछाप सामग्री विक्रय करने के आरोप में पाया गया दोषी

सिद्ध होने पर 01 अनावेदक पर 25 हजार रूपये की अर्थदण्ड शास्ति अधिरोपित

धीरज कुमार अहीरवाल । सिटी चीफ ।
दमोह, खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत मिथ्या छाप भैंस का दूध विक्रय करने पर दोष सिद्ध होने के आरोप में अपर कलेक्टर एवं न्याय निर्णयन अधिकारी मीना मसराम ने जिले के 01 अनावेदक पर 25 हजार रूपये के अर्थदण्ड की शास्ति अधिरोपित की है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी माधवी रावत (बुधौलिया) द्वारा प्रस्तुत परिवाद पर ग्राम सागौनी स्टेशन रोड गाड़ाघाट तहसील पटेरा निवासी अनावेदक पुरूषोत्तम राय पिता मलतू राय द्वारा अमानक भैंस का दूध विक्रय करने के आरोप में 25 हजार रूपये के अर्थदण्ड की शास्ति अधिरोपित की है। अधिरोपित शास्ति की राशि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मुख्य शाखा

दमोह में चालान द्वारा शीर्ष 0210-चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य 04 लोक स्वास्थ्य 104 शुल्क एवं दण्ड आदि 0754 खाद्य एवं औषधि नियंत्रण में जमा कराकर चालान की एक प्रति न्यायालय अपर कलेक्टर एवं न्याय निर्णयन अधिकारी के कार्यालय में प्रस्तुत करना होगी। अधिरोपित शास्ति की राशि 15 दिवस में जमा की जाये। नियत समयावधि में राशि जमा नहीं किये जाने पर अधिनियम की धारा 96 के तहत भू-राजस्व की बकाया की भांति वसूल की जायेगी। उन्होंने आदेशित किया है कि क्रय की गई सामग्री को अपील अवधि पश्चात विनिष्टिकरण किया जाये

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत चलाया जा रहा है शहरी स्वास्थ्य मिशन

हाई रिस्क गर्भवती महिलाओं को यूपीएचसी में मिल रही जांच एवं उपचार की सुविधा

धीरज कुमार अहीरवाल । सिटी चीफ ।
दमोह, जिला अस्पताल की ओपीडी लोड को कम करने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत शहरी स्वास्थ्य मिशन चलाया जा रहा है, जिसमें वर्तमान में एक यूपीएचसी व 6 संजीवनी क्लीनिक संचालित हो रहे है। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान-पीएमएसएमए अंतर्गत विशेष शिविर को शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बीडी कॉलोनी जटाशंकर दमोह में आयोजित किया गया। जिसमें स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉ. रजीता गांगरा व यूपीएचसी स्टाफ द्वारा आने वाली महिलाओं की जांच कर उपचार दिया गया। शिविर में 147-हितग्राहियों ने अपना पंजीयन कराया, जिसमें 72-गर्भवती महिलाएं 25-हाई रिक्स गर्भवती महिलाएं, 6-पीएनसी महिलाएं के अलावा 67 जनरल मरीजों ने अपनी जांच करायी। कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर के आदेश पर शिविर का निरीक्षण जिला पंजीयक अधिकारी मोनिका नवरंग द्वारा किया गया। जिला पंजीयक अधिकारी मोनिका नवरंग ने बताया की शिविर में आये मरीजों में से 6 को आयरन

सुक्रोज लगाया गया व अन्य मरीजों के ब्लड सेम्पल लेकर अनुबंधित संस्था को जांच हेतु भेजे गये है, जिनकी रिपोर्ट संबंधितों को अगले दो से तीन दिवस में दी जायेगी। जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. रीता चर्टर्जी ने बताया पूरे जिले में कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर के निर्देशन में प्रत्येक माह की 2,9,16 व 25 तारीख को सभी संस्थाओं में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान अंतर्गत पीएमएसएमए विशेष शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में आज यूपीएचसी जटाशंकर दमोह में आयी 25-हाई रिस्क महिलाओं की जांच के साथ इनकी निरंतर निगरानी की जा रही है, ताकि मातृ मृत्यु दर को कम किया जा सकें। साथ ही शहरी क्षेत्र मं शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र संचालित होने से जिला चिकित्सालय का कुछ ओपीडी भार कम भी होगा।

कलेक्टर द्वारा की गयी अर्थदण्ड कार्यवाही

11 एल-1 अधिकारियों के विरूद्ध हुई कार्रवाई

धीरज कुमार अहीरवाल । सिटी चीफ ।
दमोह, सीएम हेल्पलाईन पोर्टल पर माह अप्रैल 2024 की कुल लंबित शिकायतों मे से एक भी शिकायत को बंद न कराये जाने के आरोप में निराकरण प्रतिशत शून्य रहने पर संबंधित एल-1 अधिकारियों को कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर उत्तर चाहे गये थे किंतु संबंधित अधिकारियों द्वारा अपने उत्तर निर्धारित समय अवधि में प्रस्तुत नही किये गये एवं अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत उत्तर समाधान कारक नही पाये जाने के फलस्वरूप कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर ने 11 अधिकारियों के विरूद्ध अर्थदण्ड की कार्रवाई करते हुये माह जून 2024 के 01 दिवस के वेतन के बराबर की राशि रेड क्रास सोसायटी दमोह मे जमा कराये जाने निर्देश दिए हैं। जारी आदेश में अर्थदण्ड की राशि 03 दिवस के भीतर लोक सेवा प्रबंधन विभाग दमोह के कार्यालय (कक्ष क्रमांक 72, कलेक्ट्रेट) में जमा कर रेडक्रॉस सोसाइटी की रसीद प्राप्त करें अथवा रेड क्रॉस सोसायटी दमोह के बैंक खाता क्रमांक-10408898213, IFSC SBIN0003716 मे जमा कर रसीद इस कार्यालय में प्रस्तुत करेंगे।

इन अधिकारियों के विरूद्ध की गई अर्थदण्ड की कार्रवाई

जल संसाधन विभाग दमोह कार्यपालन यंत्री शुभम अग्रवाल, अनुविभागीय अधिकारी पथरिया सुशील कुमार सुहाने, अनुविभागीय अधिकारी हटा आई. डी. पाठक, अनुविभागीय अधिकारी दमोह वर्षा मिश्रा, बी.आर.सी. पथरिया जिनेन्द्र कुमार जैन, सहायक प्रबंधक हटा व्ही.पी. पटैल, सिविल इंजीनियर तेन्दूखेड़ा हिंमाशु शर्मा, सहायक प्रबंधक दमोह आनंद नेमा, सहायक प्रबंधक तेन्दूखेड़ा अक्षय सिंह बघेल, ग्रामोद्योग अधिकारी हटा प्रकाश चंद्र पटवा एवं वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी हटा माधव प्रसाद सिरवैया के विरूद्ध अर्थदण्ड की कार्रवाई की गई।

जिला प्रशासन एवं जन अभियान परिषद के मार्गदर्शन में जल गंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत ग्राम भौंरासा में हुआ स्वच्छता श्रमदान कार्यक्रम

प्राचीन तालाब को एक सप्ताह में जन सहयोग से स्वच्छ करने का ग्रामीण जनों ने लिया संकल्प

धीरज कुमार अहीरवाल । सिटी चीफ ।
दमोह, कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर द्वारा दिये गये निर्देशों के तहत मध्य प्रदेश अभियान परिषद जिला दमोह के मार्गदर्शन में जल गंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत पथरिया विकासखंड अंतर्गत सदगुवा सेक्टर के ग्राम पंचायत भौंरासा में ग्राम पंचायत एवं नवांकुर संस्था छात्र सर्व कल्याण समिति द्वारा ग्राम विकास प्रस्फुटन समिति और छात्र क्रांति दल के विशेष सहयोग से ग्रामीण जनों के साथ एक बैठक ग्राम चौपाल का आयोजन कर प्राचीन जलाशय तालाब में स्वच्छता एवं श्रमदान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसके साथ ही ग्रामीण जनों के साथ वृक्षारोपण भी किया गया।
जल गंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत जल संरचनाओं के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु 5 जून से 14 जून 2024 तक अभियान चलाया जाएगा जिसके अंतर्गत आज ग्राम भौंरासा में इस अभियान का प्रारंभ किया गया है। इस दौरान संपूर्ण ग्राम वासियों ने यह संकल्प लिया है कि हम इस अभियान के अंतर्गत जन सहयोग और जन सहभागिता से अपनी प्राचीन धरोहर इस जलाशय को साफ और स्वच्छ बनाने का काम करेंगे। स्वच्छता और श्रमदान कार्यक्रम के दौरान प्रमुख रूप से मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद जिला दमोह के समन्वयक सुशील कुमार नामदेव, ग्राम पंचायत सरपंच भारत पटेल, उप सरपंच धनीराम यादव, नवांकुर संस्था अध्यक्ष कृष्णा पटेल, ग्राम विकास प्रस्फुटन समिति अध्यक्ष भौंरासा आशीष पटेल, दिनेश कुर्मी, सीएमसीएलडीपी परामर्शदाता दिलीप कुमार पटेल, घनश्याम पटेल सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण जनों की उपस्थिति रही।

जिले की जनता अपनी-अपनी समस्याएं और शिकायतें लेकर आती हैं, यदि उनका निदान समय पर हो जाता है, तो यह प्रशासन का, सुशासन की दिशा में बढ़ाया हुआ एक बड़ा कदम

किसी मंगलवार के दिन अवकाश होता है, तो अगले दिन होगी जनसुनवाई, 11 जून से नियमित होगी जनसुनवाई

धीरज कुमार अहीरवाल। सिटी चीफ।
दमोह, निर्वाचन संपन्न होने के साथ आदर्श आचरण संहिता की अवधि समाप्त हो गई हैं। आगामी मंगलवार 11 जून से जनसुनवाई नियमित रूप से प्रारंभ हो जाएगी। जनसुनवाई को सर्वोच्च प्राथमिकता देने का निर्णय लिया गया है, यही वह व्यवस्था हैं, जहां पर जिले की जनता अपनी-अपनी समस्याएं और शिकायतें लेकर आती हैं। यदि उनका निदान समय पर हो जाता है, तो यह प्रशासन का, सुशासन की दिशा में बढ़ाया हुआ एक बड़ा कदम है, इसलिए जनसुनवाई हमारा बहुत बड़ा फोकस एरिया है, इसको बहुत सुंदृढ़ बनाने का निर्णय लिया है। इस आशय के विचार जनसुनवाई को लेकर व्यक्त किए।

अगले 11 जून से प्रात: 10 बजे से लगातार जनसुनवाई शाम तक चलेगी। पहले यह व्यवस्था थी की अलग-अलग विभागों के आधिकारी कलेक्टर कार्यालय में आकर बैठते थे, लेकिन अब शासन के निर्देशों के अनुरूप यह व्यवस्था करने के आदेश जारी कर दिए हैं कि जिला कलेक्टर कार्यालय के अलावा अधिकारी, कार्यालय प्रमुख जिला कार्यालय और विकासखंड कार्यालय में अनिवार्य रूप से जनसुनवाई करेंगे, वे वहीं रहेंगे, वहीं पर बैठकर जनसुनवाई करेंगे। कलेक्टर कार्यालय में जिला कलेक्टर और जिला कलेक्टर की अनुपस्थिति में अपर कलेक्टर या डिप्टी कलेक्टर जो ऑथराइज्ड होगें, वे जनसुनवाई करेंगे। इस प्रकार यह एक बड़ा परिवर्तन है जिसमें जिले के अधिकारियों को यहां पर नहीं बैठना होगा, वे अपने कार्यालय में बैठेंगे और वहीं पर लोगों की समस्याओं को सुनेंगे, इससे शासन के निर्देशों के अनुरूप विकासखंड स्तर तक लोगों की जनसुनवाई हो सकेगी और उनको जिले में अपनी समस्याओं को लेकर नहीं आना पड़ेगा।

एक दूसरा फायदा यह होगा कि जो लोग जिले में अपनी समस्या लेकर आते हैं उनके समाधान के लिए विकासखंड स्तर पर या दूसरे कार्यालय में तत्काल चर्चा की जा सकेगी और अधिकारी उनका समाधान करने की स्थिति में रहेंगे। यदि आवश्यकता पड़ेगी तो संबंधित आवेदकों को तुरंत उन अधिकारियों के ऑफिस भेजा जा सकेगा, जिससे उनका समाधान वे ऑफिस में रहकर कर सकेंगे।

कुछ ऐसे विभाग है जिनके दफ्तर जिले में सभी जगह फैले हुए हैं, ग्रामीण विकास, राजस्व विभाग, नगरीय विकास और पुलिस इनके दफ्तर अलग-अलग जगह पर भी हैं, इन विभागों के एक-एक व्यक्ति को नोडल बनाया गया है और यह जो चार नोडल रहेंगे, यह यहां आएंगे उनके विभागों से संबंधित जो विषय हैं, वह कंसोलिडेटेड करके अपने पास से उनके पेपर को ले जाएंगे और कोऑर्डिनेटर करेंगे कि इन समस्याओं का समाधान जितना जल्दी हो सके, वे करेंगे।

पुलिस विभाग, नगरीय विकास, राजस्व विभाग और ग्रामीण विकास के एक-एक व्यक्ति रहेंगे। एसडीएम जनसुनवाई का एक लॉगइन होता है और प्रतिदिन एसडीएम लॉगइन पर जो-जो उनके विकासखंड या अनुविभाग, तहसील स्तर पर जनसुनवाई में शिकायतें आयेंगी, एसडीएम का यह दायित्व होगा कि वह अपनी लॉगइन से इन सभी की एंट्री करायें। जनसुनवाई में जितने भी शिकायतें आती हैं वह ऑटोमेटेकली सीएम हेल्पलाइन में जुड़ जाएंगी, इस प्रकार के स्ट्रक्चर पर हम काम करेंगे। सभी संबंधितों को निर्देशित कर दिया गया है की जनसुनवाई में जितने लोग भी आते हैं विकासखंड कार्यालय और जिला के अन्य कार्यालय में प्रात- 10 बजे से दोपहर 01 बजे तक जनसुनवाई होगी, कलेक्टर कार्यालय में जितने हितग्राही आएंगे उनके हिसाब से जनसुनवाई और लंबी भी चल सकती है। यदि किसी मंगलवार के दिन अवकाश होता है, तो अगले दिन जनसुनवाई की जायेगी, इसके लिए समय पर लोगों को अवगत कराया जाएगा और सभी कार्यालय को निर्देशित किया गया है कि जो भी आवेदक आयेंगे उन्हें सम्मानपूर्वक बैठने, पीने के पानी की और अन्य बुनियादी सुविधाओं सहित अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाए। प्रयास होगा की समस्याओं का निराकरण जितना जल्दी हो सके और पात्रता के अनुसार यदि मौके पर ही हो सके तो इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता है। जनसुनवाई को सुशासन का एक बहुत बड़े उपकरण के रूप में जिले में एस्टेब्लिश कर पाए और बेहतर से बेहतर लोगों को सुविधा दे पाए।

प्रयास है एक व्यक्ति यदि एक बार जनसुनवाई में आता है तो उसको दोबारा जनसुनवाई में लौटकर न आना पड़े, हम उसका समाधान इस जनसुनवाई में ही निकालें यदि उसका समाधान संभव है तो, इसलिए यह व्यवस्था की गई है।

कलेक्टर कार्यालय में ग्राउंड फ्लोर पर जनसुनवाई रूम में जिला कलेक्टर सुबह से जनसुनवाई के लिए बैठेंगे। अभी तक यह होता था कि कॉरिडोर में लोग बैठते थे, अब कॉरिडोर की बजाय जहां जनसुनवाई हो रही है वहीं पर चेयर्स लगाई जाएगी, उसी कक्ष में सभी आवेदक बैठेंगे, वहां पर उनके लिए पेयजल, शौचालय और सारी मूलभूत व्यवस्थाएं हैं, वह माकूल की जाएंगे और कोशिश की जाएगी एक-एक आवेदन को ध्यान से सुना जाए और उनको पर्याप्त समय दिया जाए, इसलिए टोकन आधारित व्यवस्था रहेगी। पहले आओ पहले पाओ के आधार पर टोकन मिलेगा, सभी लोग अपनी सीट पर धैर्य से बैठेंगे, अपनी बारी आने का इंतजार करेंगे जैसे ही उनके टोकन की पुकार लगेगी वह आकर कलेक्टर के सामने अपनी बात रख सकते हैं, इसके लिए कलेक्टर की कुर्सी के सामने उनकी कुर्सी लगाई जाएगी और वह अपनी बात कलेक्टर के समक्ष रख सकेंगे।

जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत राघौगढ़ क्षेत्र की पुरानी जल संरचनाओं को बनाया जा रहा है उपयोगी

गुना
म.प्र.शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग भोपाल के निर्देशानुसार एवं कलेक्टर डॉ. सतेन्द्र सिंह के निर्देशन एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री प्रथम कौशिक के मार्गदर्शन में जल गंगा संर्वधन अभियान दिनांक 05 जून 2024 से 16 जून 2024 तक चलाया जा रहा हैं। जिसमें पुरानी जल संरचनाऐं जो अनुपयोगी हैं उनके जीर्णोद्धार एवं मरम्मत कार्य कराया जाकर अनुपयोगी संरचनाओं को उपयोगी बनाया जा रहा है । मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत राघौगढ़ श्री शैलेंद्र यादव द्वारा बताया गया कि आज जनपद पंचायत राघौगढ़ की क्षैत्रांतर्गत ग्राम पंचायत परेवा, नागनखेड़ी, ककवासा, भुलाएं, बालाभेंट में चेक डेम मरम्मत कार्य, ग्राम पंचायत पीपलखेडी, मोरवास, गाड़ेर, दीतलवाड़ा, बड़ा अमल्या, मह्रू, परसोलिया, रामनगर, दुहावड़, देहरी आदि में सार्वजनिक कूप मरम्मत एवं साफ सफाई कार्य, ग्राम पंचायत सुन्दरखेडी एवं दीतलवाडा, बंजला, भदोडी, बेरवास, बरसत, भुलाएं, बालाभेन्ट, गादेर में तालाब मरम्मत कार्य, ग्राम पंचायतों में कराया जा रहा है। साथ ही ग्राम पंचायतों में जल संरक्षण संवर्धन अभियान के प्रचार प्रसार हेतु दीवार लेखन के माध्यम से नारे लेखन का कार्य किया जा रहा है ।

शासकीय आईटीआई में प्रवेश पंजीयन एवं च्वाईस फिलिंग 10 जून 2024 तकइंदौर, रविवार , 09 जून 2024

झाबुआ - जिले में स्थित शासकीय आईटीआई झाबुआ, बामनिया, थांदला एवं मेघनगर में सचालित एनसीवीटी/एससीवीटी के पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु आवेदक अपना ऑनलाईन पंजीयन एवं च्वाईस फिलिंग 10 जून तक कर सकते हैं। 01 अगस्त 2024 को 14 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले अभ्यर्थी 10 जून तक इंटरनेट के माध्यम से अथवा ऑनलाईन सहायता केन्द्रों से विभागीय पोर्टल 222.स्र्ह्मश्र.द्बह्ल.द्दश1.द्बठ्ठ पर आवेदन कर सकते हैं। शासकीय आईटीआई में प्रवेश लेने वाले आवेदकों को शासन दवारा छात्रवृति, विभागीय मेरिट छात्रवृति, प्रतिष्ठित संस्थानो औद्योगिक इकाईयों में ऑन द जॉब ट्रेनिंग के साथ स्टाइपेंड, पॉलिटेक्निक कॉलेज में लेटरल एंट्री के माध्यम से द्वितीय वर्ष में प्रवेश, ग्लोबल स्किल पार्क भोपाल में संचालित एडवांस कोर्सेस में सीधे प्रवेश एवं दो वर्षीय इंजीनियरिंग ट्रेड में आईटीआई उत्तीर्ण अभ्यर्थी केवल दो विषय हिन्दी एवं अंग्रेजी की एमपी बोर्ड से परीक्षा देकर 12 वी की समकक्षता योजना का लाभ ले सकते है। आईटीआई उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के लिए शासकीय विभागों, अर्धशासकीय औद्योगिक संगठनों, रेलवे, भेल, सेल, गेल, कोल माइन्स, दूरसंचार कंपनियों, आयुध निर्माणी, आर्मी, पुलिस, सुरक्षा बल, विंड-सोलर-हाइडल पॉवर जनरेशन एवं वितरण कंपनियों इत्यादि में अप्रेंटिसशिप एवं रोजगार प्राप्ति के अनेकों अवसर उपलब्ध है।

विलुप्त होती बावड़ी को जल गंगा संवर्धन अभियान से मिला नवजीवन

बालाघाट

3 घन्टे श्रमदान से 200 वर्ष पुरानी बावड़ी से निकला पानी

डस्टबिन की तरह हो रही थी उपयोग

सुबह 9 बजे से 4 बजे तक किया श्रमदान जल गंगा संवर्धन अभियान ऐसे जल स्त्रोतों को भी पुनर्जीवन देने के लिए प्रारम्भ हुआ है। जो पहले कभी जल तृप्ति के महत्वपूर्ण आधार हुआ करते थे। लेकिन आधुनिकता ने ऐसे जल स्त्रोतों को पीछे छोड़ नवीन धारा में बहने लगें। लांजी नगर के श्रीराम मंदिर प्रांगण में करीब 200 वर्ष पुरानी बावड़ी है, जो आज से पहले डस्टबिन की तरह उपयोग में आ रही थी। इसमें पूजन हवन और भंडारे से बचा कूचा सामान डाला जा रहा था। लेकिन जल गंगा संवर्धन अभियान में अचानक इस पुराने जल स्त्रोत की ओर ध्यान गया। एसडीएम श्री प्रदीप कौरव ने बताया कि शनिवार सुबह से करीब 3 घंटे यहाँ व्यापारी वर्ग, शासकीय अधिकारियों और पार्षदगणों ने श्रमदान कर करीब 2 टन कचरा और मिट्टी निकाली। इसके बाद बावड़ी पुनर्जीवित होने लगी। पानी निकलने लगा। श्रमदान के लिए नगर परिषद के साथ रूपरेखा बनाई गई। सुबह से ही स्वयं विधायक श्री राजकुमार कर्राहे ने भी अभियान में शामिल होकर जनप्रतिनिधियों को प्रेरित किया। साथ ही नपरि के पार्षदगणों व अध्यक्ष श्रीमती रेखा ताराचंद व उपाध्यक्ष श्री संदीप रामटेककर भी शामिल हुए।

पंडित परिवार के आपसी विवाद से लुप्तप्राय होती गई एसडीएम श्री कौरव ने बताया कि जनवरी तक इस बावड़ी में पानी बना रहता है। मंदिर प्रांगण स्थित इस बावड़ी के विषय मे बहुत कम लोगों को जानकारी है। पूर्व में भी इस बावड़ी के पुनरुद्धार के लिए कार्य योजना बनाई गई थी। मगर पंडित परिवारो के आपस विवाद के कारण कार्य नही हो सका। लेकिन इस अभियान में इसे प्रमुखता से लिया गया। करीब 10 फिट तक गाद भर गई। जिसे श्रमदान से निकाला गया। श्रमदान सुबह 9 बजे से प्रारम्भ हुआ जो 4 बजे तक चला। बीच मे 1 घंटे आराम के बाद पुन: सफाई में जुटे। हालांकि 3 घंटे में 5 फिट तक ही पहुँच सकें।

जाली और शेड लगाकर सुरक्षित रखा जाएगा एसडीएम श्री कौरव ने कहा कि अभी तो बावड़ी में करीब 15 फिट तक कि गाद निकाली जाएगी। इसके बाद सुरक्षित रखने के लिए ऊपर जाली और सीढ़ियों पर शेड बनाया जाएगा। अगर पानी पेयजल के योग्य रहा और नपा चाहे तो आगे उपयोगी बना सकेंगे।

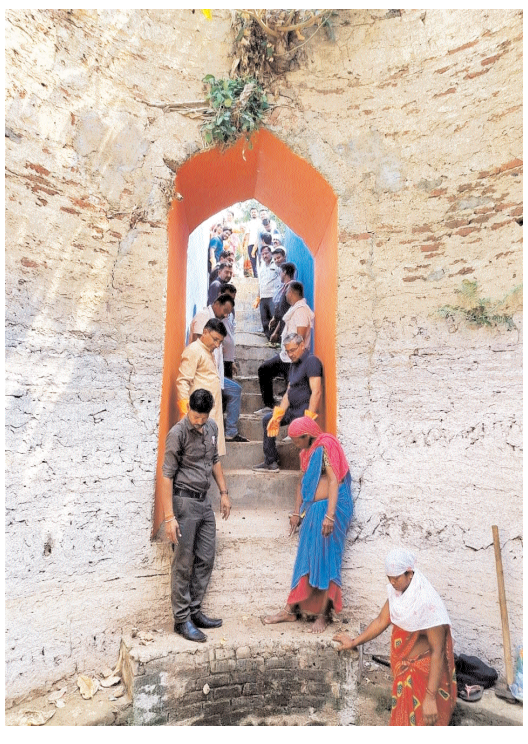

इजराइल ने हमास के चंगुल से चार बंधकों को छुड़ाया

IDF द्वारा गाजा में किए गए हमले में 210 फिलिस्तियों की मौत

यरूशलम: इजराइल ने हमास के साथ युद्ध शुरू होने के बाद से बंधकों को बचाने के लिए शनिवार को अपना सबसे बड़ा अभियान चलाया और मध्य गाजा में भीषण लड़ाई के बीच अपहर्ताओं के चंगुल से चार इजराइली लोगों को सकुशल मुक्त करा लिया। इसके साथ ही मध्य गाजा में भीषण लड़ाई में बच्चों सहित कम से कम 210 फलस्तीनी मारे गए। मुक्त कराए गए लोगों का फलस्तीनी चरमपंथी संगठन हमास ने सात अक्टूबर को किए गए हमले के दौरान अपहरण कर लिया था। इजराइली सेना ने कहा कि उसने दिन के दौरान चलाए गए अभियान में नुसीरात में एक जटिल अभियान में नोआ अर्गामानी (25), अल्मोग मीर (21), एंड्री कोज़लोव (27) और श्लोमी जिव (40) को मुक्त करा लिया। इसने कहा कि बंधकों को नुसीरात के मध्य में स्थित दो अलग-अलग स्थानों से बचाया गया और वे सभी ठीक हैं। इजराइली सेना ने कहा कि जिन चार बंधकों को छुड़ाया गया उन्हें हेलीकॉप्टर से चिकित्सीय जांच के लिए ले जाया गया और वे 246 दिन तक अपहर्ताओं के चंगुल में रहने के बाद अपने प्रियजनों से मिल पाए। अर्गामानी का तीन अन्य लोगों की तरह ही एक संगीत समारोह से अपहरण कर लिया गया था। उनके अपहरण का वीडियो सबसे पहले आए विभिन्न वीडियो में शामिल था। इस वीडियो में वह एक मोटरसाइकिल पर दो लोगों के बीच बैठी दिखी थीं जिसमें वह ''मुझे मत मारो चिल्लाते हुए सुनाई दी थीं। उनकी मां लियोरा को चौथे चरण का ब्रेन कैंसर है और अप्रैल में उन्होंने एक वीडियो जारी कर मरने से पहले अपनी बेटी को देखने की अपील की थी। खुशी से लबरेज अर्गामानी ने प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से फोन पर बात की। सरकार द्वारा जारी किए गए एक वीडियो संदेश में वह उनसे यह कहती सुनाई देती हैं कि वह बहुत खुश हैं और इतने लंबे समय से उन्हें हिब्रू भाषा सुनने को नहीं मिली। इस बीच, नेतन्याहू ने एक बयान में कहा कि इजराइल आतंकवाद के सामने झुकता नहीं है और सभी बंधकों को मुक्त कराए जाने तक लड़ाई जारी रहेगी। इजराइल के रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने कहा, ''अभियान साहसिक था। शानदार ढंग से इसकी योजना बनाई गई और असाधारण तरीके से इसे अंजाम दिया गया। इस बीच, अमेरिका के एक अधिकारी ने कहा कि एक अमेरिकी इकाई ने बंधकों का पता लगाने और उन्हें छुड़ाने की पूरी प्रक्रिया में सलाह एवं सहायता प्रदान की। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार, मध्य गाजा में जिस जगह से बंधकों को बचाया गया वहां शनिवार को भीषण लड़ाई हुई और बच्चों सहित कम से कम 94 फलस्तीनी मारे गए। मध्य गाजा स्थित एक अस्पताल के अधिकारी खलील देगरान ने बताया कि डेर अल बलाह स्थित अल-अक्सा अस्पताल में लगभग 100 फलस्तीनियों के शव लाए गए और 100 से अधिक घायल भी लाए गए। इजराइल का कहना है कि 130 से अधिक बंधक अभी भी बचे हैं जिनमें से लगभग एक चौथाई को मृत माना जा रहा है। बंधकों की वापसी के मुद्दे पर इजराइल में लोगों में रोष गहराता जा रहा है। युद्ध शुरू होने के बाद से अभियान चलाकर बचाए गए कुल बंधकों की संख्या सात हो गई है। हमास ने सात अक्टूबर को दक्षिणी इजराइल पर अचानक हमला कर लगभग 1200 लोगों की हत्या कर दी थी और 250 लोगों का अपहरण कर लिया था। इसके बाद इजराइल-हमास के बीच युद्ध शुरू हो गया। नवंबर में एक सप्ताह के संघर्षविराम के दौरान हमास द्वारा बंधकों में से लगभग आधे लोगों को रिहा कर दिया गया था।

भारतीय राजदूत ने कहा- हमारे मतदान प्रतिशत और गठबंधन की गति ने यूरोप को किया प्रभावित

इंटरनेशनल डेस्क: बुल्गारिया में भारतीय राजदूत संजय राणा ने कहा है कि भारत में चुनाव के मतदान प्रतिशत और गठबंधन बनाने की गति ने बुल्गारिया जैसे यूरोपीय देशों को प्रभावित किया है। बुल्गारिया में इस सप्ताहांत में मतदान प्रक्रिया समाप्त हो रही है जिसमें मतदाता यूरोपीय संसद के सदस्यों और अपनी नेशनल असेंबली के सदस्यों का चुनाव करेंगे। रविवार को बुल्गारिया में होने वाले चुनावों से पहले एक साक्षात्कार में भारतीय राजदूत संजय राणा ने आशा व्यक्त की कि परिणाम से द्विपक्षीय सहयोग बढ़ेगा। ये चुनाव भारत में सात चरणों में लोकसभा चुनाव संपन्न होने के कुछ दिन बाद हो रहे हैं। राजदूत राणा ने कहा, कई यूरोपीय देशों की तरह बुल्गारिया भी चुनावों में कम मतदान की समस्या का सामना कर रहा है और वे सभी भारतीय चुनावों में अच्छी संख्या में हुए मतदान के लिए मुझे बधाई देते हैं। भारत में हाल ही में संपन्न हुए लोकसभा चुनावों में 65.79 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया। राजदूत ने साक्षात्कार में कहा, यहां के लोग इस बात से भी हैरान हैं कि भारत में गठबंधन कितनी जल्दी बनते हैं और हमारी राजनीति कितनी स्थिर होती है। उन्होंने कहा, हमारे पास बड़ी संख्या में राजनीतिक दल और मतदाता हैं लेकिन सरकार का गठन अपेक्षाकृत तेज़ है और बुल्गारिया में हम जो देखते हैं उसकी तुलना में हमारी सरकारें बहुत स्थिर होती हैं। राजदूत ने कहा, भारत और बुल्गारिया के बीच बहुत घनिष्ठ और मधुर संबंध हैं और जब यहां स्थिर सरकार होगी, तो हम उच्च स्तरीय यात्राओं और प्रतिनिधिमंडलों, राजनीतिक तथा व्यापारिक दोनों तरह के प्रतिनिधिमंडलों का अधिक आदान-प्रदान देखने की उम्मीद करते हैं एवं कई समझौता ज्ञापनों और समझौतों पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद करते हैं जिनकी हम योजना बना रहे हैं।

चीन का नेपाल में नया खेलः तेल और गैस की खोज के लिए काठमांडू को फंसाया

बीजिंग: नेपाल, जो पहले कई आर्थिक और भू-राजनीतिक कारकों के कारण चीन की ओर पूरी तरह से झुकाव रखने में हिचकिचा रहा था, अब अपने बड़े उत्तरी पड़ोसी की ओर झुकता हुआ दिखाई दे रहा है, जिससे उसे हिमालयी देश के राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र में अपनी उपस्थिति को और बढ़ाने का अवसर मिल रहा है। फिर भी नेपाल पर नज़र रखने वालों को सबसे ज़्यादा चिंता इस बात की है कि हिमालयी देश चीन को एक ऐसे क्षेत्र में प्रवेश करने का मौक़ा दे रहा है जो अब तक अछूता था- तेल और गैस की खोज में। 1985 में, नेपाल ने तेल और गैस की खोज के लिए विदेशी कंपनियों को आमंत्रित किया था। शेल और ट्राइटन एनर्जी ने भूकंपीय सर्वेक्षण किया था और तेल की संभावना का परीक्षण करने के लिए 3520 मीटर का कुआँ खोदा था, लेकिन इससे कोई परिणाम नहीं निकला। यहाँ तक कि चीन बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को लेकर नेपाली लोगों में असंतोष को बढ़ावा दे रहा है। मई 2017 में, प्रचंड की अध्यक्षता वाले नेपाल और चीन ने BRI पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे। दोनों विदेशी कंपनियों ने 1990 में नेपाल में तेल और गैस अन्वेषण बोलियों से अपना नाम वापस ले लिया था। द राइजिंग नेपाल ने कहा कि हालांकि, मई 2024 के शुरुआती हफ़्तों में, लगभग 20 चीनी इंजीनियरों की एक टीम ने 45 नेपाली तकनीशियनों के साथ दैलेख में तेल की खुदाई शुरू की, जो काठमांडू से 644 किलोमीटर से अधिक दूर है। नेपाली सरकार समर्थित अंग्रेजी भाषा के अख़बार ने कहा कि पेट्रोलियम उत्पादों की खोज के लिए उपकरण और उपकरण इस साल अप्रैल में ट्रकों में चीन से हिमालयी देश में पहुँचे। एक अन्य नेपाली अख़बार, कांतिपुर ने कहा कि चीनी और नेपाली तकनीशियनों ने भूकंपीय, भूवैज्ञानिक, मैग्नेटोटेल्यूरिक और भू-रासायनिक नमूना चार सर्वेक्षण किए। कांतिपुर ने कहा कि उन्होंने दूसरे चरण में तेल ड्रिल मशीनों के माध्यम से अन्वेषण के लिए जाने से पहले एक व्यवहार्यता अध्ययन भी किया। द राइजिंग नेपाल के अनुसार, अन्वेषण के लिए, नेपाल सरकार के खान और भूविज्ञान विभाग और चीनी सरकार की भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण कंपनी के बीच 2019 में पेट्रोलियम उत्पादों की खोज और निष्कर्षण के लिए वित्तीय और तकनीकी सहायता के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। यह 1985 के बाद से नेपाल में पहला तेल और गैस अन्वेषण होगा, जब हिमालयी देश में तेल की खोज के लिए इसी तरह के प्रयास से कोई परिणाम नहीं निकला था।पर्यवेक्षक इस नवीनतम परियोजना को चीन द्वारा नेपाल में अपने प्रभाव को और बढ़ाने के प्रयास के रूप में देखते हैं, जो एक छोटा हिमालयी राष्ट्र है, जिसे वर्तमान में पुष्प कमल दहल प्रचंड द्वारा चलाया जाता है, जिनका चीन के प्रति झुकाव सर्वविदित है। इस वर्ष मार्च में, उन्होंने नेपाली कांग्रेस, एक उदार लोकतांत्रिक पार्टी को छोड़कर, अपनी सरकार चलाने के लिए चीन के कट्टर सहयोगी के पी शर्मा ओली, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल (यूनाइटेड मार्क्सवादी-लेनिनवादी) के प्रमुख को नियुक्त किया। चीन ने प्रचंड के नेतृत्व वाली कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल (माओवादी केंद्र) और के पी शर्मा ओली के नेतृत्व वाली कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल (यूनाइटेड मार्क्सवादी-लेनिनवादी) की गठबंधन सरकार को बधाई देने में देर नहीं लगाई।यह कम्युनिस्ट गठबंधन के पुनरुत्थान का प्रतीक है, जिसे पहली बार 2017 में काठमांडू में तत्कालीन चीनी राजदूत यू होंग की सहायता से नेपाल में बनाया गया था। तब चीन ने नेपाल के राजनीतिक मामलों में अपने हस्तक्षेप से इनकार किया था।

चीन ने हिमालयी राष्ट्र की 36 हेक्टेयर भूमि पर किया अतिक्रमण

इसी तरह का दृष्टिकोण तब अपनाया गया जब मीडिया ने दावा किया कि मार्च 2024 में नेपाल में प्रचंड के नेतृत्व वाली नई गठबंधन सरकार के गठन में इसने पर्दे के पीछे से भूमिका निभाई। नवंबर 2022 में नेपाल के कृषि मंत्रालय द्वारा जारी एक सर्वेक्षण दस्तावेज़ के अनुसार, चीन ने उत्तरी सीमा पर 10 स्थानों पर हिमालयी राष्ट्र की 36 हेक्टेयर भूमि पर अतिक्रमण किया है। निक्की एशिया ने कहाक्योंकि, सरकार के गठन के तुरंत बाद, एक चीनी सैन्य प्रतिनिधिमंडल ने नेपाल का दौरा किया और बाद में रक्षा सहयोग को बढ़ाने का वादा किया । जबकि इसने नेपाल पर अपनी पकड़ मजबूत करने के बीजिंग के प्रयास के बारे में स्पष्ट रूप से संकेत दिया, इसने हिमालयी राष्ट्र में जीवन के हर पहलू को प्रभावित करने के पूर्वी एशियाई देश के प्रयास के बारे में भी संकेत दिया।

नेपाली लोगों में असंतोष

चीन बेल्ट एंड रोड पहल को लेकर नेपाली लोगों में असंतोष पैदा कर रहा है। मई 2017 में प्रचंड की अगुआई में नेपाल और चीन ने बीआरआई पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे। इस समझौते को हिमालयी राष्ट्र ने नेपाल-चीन संबंधों में एक महत्वपूर्ण क्षण के रूप में सराहा था क्योंकि उसे उम्मीद थी कि यह देश में चीनी निवेश को आकर्षित करेगा।

पाकिस्तान में पोलियो रोधी अभियान को झटका

2024 में चौथा मामला आया सामने देश- दुनिया की बढ़ी चिंता

इस्लामाबाद: पाकिस्तान जो अपने पड़ोसी अफ़गानिस्तान के साथ दुनिया के दो बचे हुए पोलियो-स्थानिक देशों में से एक है, ने 16.5 मिलियन से ज़्यादा 5 साल से कम उम्र के बच्चों को टीका लगाने के लिए राष्ट्रव्यापी पोलियो टीकाकरण अभियान शुरू किया है। दक्षिण एशियाई देश में इस साल के जंगली पोलियोवायरस का चौथा मामला सामने आने के बाद, इस बीमारी को खत्म करने के देश के प्रयासों को झटका लगा है। ड्ड ।।ह ने कहा कि अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के इलाकों में जंगली पोलियोवायरस का स्थानिक संक्रमण जारी है, साथ ही कहा कि इन बचे हुए इलाकों में पोलियो को रोकने में विफलता के परिणामस्वरूप बीमारी का वैश्विक स्तर पर फिर से उभार हो सकता है। पाकिस्तान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि पाँच दिवसीय टीकाकरण अभियान इस महीने के आखिर में ईद-उल-अज़्हा के आगामी मुस्लिम त्योहार के अवसर पर पूरे देश में होने वाले बड़े पैमाने पर सार्वजनिक आंदोलन से पहले शुरू किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार, टीकाकरण अभियान पाकिस्तान के 66 जिलों में चलाया जाएगा, जिसमें 33 जिलों में पूर्ण टीकाकरण होगा, जबकि 30 जिलों में आंशिक टीकाकरण होगा। देश के स्वास्थ्य मंत्रालय का हवाला देते हुए, मीडिया रिपोर्टों में कहा गया है कि राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान संघीय राजधानी इस्लामाबाद, दक्षिण-पश्चिमी बलूचिस्तान प्रांत के 20 जिलों, उत्तर-पश्चिमी खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के 23 जिलों, दक्षिणी सिंध प्रांत के 16 जिलों और पूर्वी पंजाब प्रांत के छह जिलों पर केंद्रित है। डॉन की एक रिपोर्ट के अनुसार, 2024 का चौथा पोलियो मामला शनिवार (1 जून) को सिंध प्रांत के शिकारपुर जिले से सामने आया। डॉन ने बताया कि पोलियोवायरस का नवीनतम मामला तब सामने आया जब पाकिस्तान सरकार ने हाल ही में पोलियो उन्मूलन कार्यक्रम के नए प्रमुख की नियुक्ति की, उनके पूर्ववर्ती ने सप्ताह के दौरान पद छोड़ दिया।इस साल की शुरुआत में, बलूचिस्तान प्रांत से पोलियोवायरस के तीन मामले सामने आए थे। इस्लामाबाद में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के अनुसार, पिछले तीन मामलों की तरह ही यह नया मामला भी टाइप-1 वाइल्ड पोलियोवायरस का था। वाइल्ड पोलियोवायरस के तीन सीरोटाइप हैं - टाइप 1 टाइप 2 और टाइप 3 और उनमें से दो - WPVw और WPV3 - का उन्मूलन किया जा चुका है, जबकि WPVv के उन्मूलन के लिए वैश्विक प्रयास चल रहे हैं, जो अभी भी दो पड़ोसी देशों - पाकिस्तान और अफगानिस्तान में स्थानिक है। हालांकि प्रति वर्ष रिपोर्ट किए गए मामलों की संख्या में गिरावट आई है। आंकड़ों के अनुसार, 2019 में पाकिस्तान में वाइल्ड पोलियोवायरस के कुल मामलों की संख्या 147 थी, जबकि 2020 में 84, 2021 में एक, 2022 में 20, 2023 में छह और 2024 में अब तक चार मामले सामने आए हैं। पाकिस्तान में पोलियो टीकाकरण अभियान 1974 में शुरू हुआ था, हालांकि आधिकारिक तौर पर उन्मूलन के प्रयास 1994 में शुरू हुए थे, और पिछले दशक में 100 से अधिक टीकाकरण दौर चलाए जाने के बावजूद संक्रमण स्थानिक बना हुआ है, रिपोर्ट में कहा गया है।

सोनिया गांधी सर्वसम्मति से कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष चुनी गईं, बोलीं- खड़गे के नेतृत्व में हम डटे रहे

नेशनल डेस्क: कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी को शनिवार को एक बार फिर से पार्टी संसदीय दल (सीपीपी) का प्रमुख चुना गया। इस मौके पर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर करारा प्रहार किया और कहा कि लोकसभा चुनाव में मोदी की ''राजनीतिक और नैतिक हार हुई है तथा उन्होंने नेतृत्व करने का अधिकार खो दिया है। कांग्रेस नेताओं ने बताया कि संविधान सदन (पुराने संसद भवन) के केंद्रीय कक्ष में हुई कांग्रेस संसदीय दल की बैठक में पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने सोनिया गांधी को सीपीपी प्रमुख नियुक्त करने का प्रस्ताव पेश किया, जिसका पार्टी के तीन सांसदों गौरव गोगोई, तारिक अनवर और के. सुधाकरन ने अनुमोदन किया। फिर से सीपीपी प्रमुख चुने जाने पर सोनिया ने पार्टी नेताओं का आभार जताया और कहा कि कांग्रेस ने इस चुनाव में अपनी दृढ़ता का परिचय दिया है। उन्होंने यह दावा भी किया कि लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी की राजनीतिक और नैतिक हार हुई है तथा ऐसे में उन्होंने न सिर्फ जनादेश बल्कि नेतृत्व करने का अधिकार भी खो दिया है। सोनिया ने कहा, देश की जनता ने विभाजन की राजनीति और तानाशाही को खारिज करने के लिए निर्णायक वोट दिया है। उन्होंने संसदीय राजनीति को मजबूत करने और संविधान की रक्षा के लिए मतदान किया। उन्होंने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा ऐतिहासिक आंदोलन थे, जिन्होंने पार्टी में हर स्तर पर नयी जान फूंकी। सोनिया ने कहा कि राहुल गांधी अभूतपूर्व व्यक्तिगत व राजनीतिक हमलों का मुकाबला करने की अपनी प्रतिबद्धता के लिए विशेष धन्यवाद के पात्र हैं।

भारतीय वायुसेना में शामिल हुए इजरायली मिसाइल रैंपेज

सुपरसोनिक गति से मार करने में सक्षम

इंटरनेशनल डेस्क: भारत अपनी सैन्य क्षमता को मजबूत करने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है। अपने लड़ाकू विमानों के बेड़े की मारक क्षमता को बढ़ाने के लिए भारतीय वायुसेना ने रैम्पेज लंबी दूरी की सुपरसोनिक हवा से जमीन पर मार करने वाली मिसाइलों को शामिल किया है, जो लगभग 250 किलोमीटर की दूरी तक के लक्ष्यों को भेद सकती हैं। भारतीय वायुसेना में हाई-स्पीड लो ड्रैग-मार्क 2 मिसाइल के नाम से जानी जाने वाली इस मिसाइल का इस्तेमाल इजरायली वायुसेना ने हाल ही में ईरानी ठिकानों पर किए गए हमलों में बड़े पैमाने पर किया था। रक्षा सूत्रों ने बताया कि भारतीय वायुसेना ने अपने रूसी विमान बेड़े में रैम्पेज को शामिल किया है, जिसमें सुखोई-30 एमकेआई और मिग-29 लड़ाकू विमानों के साथ-साथ जगुआर लड़ाकू विमान भी शामिल हैं। स्वदेश में रक्षा उपकरण बनाने के साथ मित्र देशों से भी अत्याधुनिक मिसाइलें और सैन्य उपकरण खरीद कर भी लड़ाकू विमानों के बेड़े की मारक क्षमता बढ़ाई जा रही है। इसी सिलसिले में वायु रक्षा प्रणाली को चकमा देने वाली इजरायली रैम्पेज मिसाइलों को भारतीय वायुसेना और नौसेना के बेड़े में शामिल किया गया है। सुपरसोनिक या आवाज से अधिक गति वाली

रैम्पेज 250 किलोमीटर तक लक्ष्य को ध्वस्त करने में सक्षम है। वायुसेना ने सुखोई -30 एमकेआई और मिग -29, जगुआर लड़ाकू विमानों को रैम्पेज मिसाइलों से लैस किया है। नौसेना ने मिग-29 के नौसैनिक लड़ाकू विमानों के लिए मिसाइलों को अपने बेड़े में भी शामिल किया है। वायुसेना अब इस बात पर भी विचार कर रही है कि क्या मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत रैम्पेज को बनाया जा सकता है। हवा से जमीन पर मार करने वाली रैम्पेज मिसाइलों के शामिल होने से भारतीय लड़ाकू विमानों की मारक क्षमता और बढ़ गई है। 2019 में बालाकोट हवाई हमले में इस्तेमाल की गई स्पाइस-2000 की तुलना में यह मिसाइल अधिक दूरी तक मार कर सकती है। हाई-स्पीड लो ड्रैग-मार्क 2 मिसाइल के रूप में जानी जाने वाली रैम्पेज मिसाइल को इजरायल ने विकसित किया है।

स्वामी, प्रकाशक एवं मुद्रक श्रीमती ज्योती मिश्रा द्वारा कॉम्पेक प्रिंटर्स प्रा. लि. फ्री प्रेस हाउस 3/54, प्रेस कॉम्पलेक्स, ए.बी. रोड, इंदौर से मुद्रित एवं 45ए गुप्ता चैम्बर पहली मंजिल जावरा कंपाउंड इंदौर, (म.प्र.) से प्रकाशित।
प्रधान सम्पादक : अशीष मिश्रा आर.एन.आई. पंजीयन क्रमांक : एमपी/एच/आइएन 2009/34385 फोन नं : 0731-4202569 फैक्स नं : 0731-4202569